in higher education is very high in Tamil Nadu. I appreciate what the hon. Member here said. But it was because of our former Chief Ministers, *Puratchi Thalaivar*, MGR, Jayalalitha and Edappadi Palanisamy that more engineering colleges were established. ...*(Interruptions)*... Now, I wish to talk about rape cases in Tamil Nadu. The number of cases of rape has increased in Tamil Nadu. If you take into account the statistics in Tamil Nadu after the new Government assumed office, rape cases have increased. ...*(Interruptions)*... I have got limited time.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.)*

Sir, I appreciate the demand for more money for Tamil Nadu, but the present DMK Government has failed to fulfil the promises made at the time of elections. Four years are over. Electricity bills have increased, property tax has increased and registration fee has increased. The present DMK Government has failed to fulfil the election promises. Coming to the housing scheme, the Central Government as well as the State Governments are providing funds, but the money is not sufficient. The money allotted for each house is very less. For better quality, the allocation needs to be enhanced. Poor people are not able to get good houses and are suffering. Our leader, Edappadi Palanisami, has always insisted that the Central Government as well as the State Government must increase the allocation for construction of houses for the poor people, especially those living in the rural areas, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, so that they get good houses. I would request the Minister to consider all these points. Thank you, Sir.

Panel of Vice-Chairpersons

MR. CHAIRMAN: Shri Ramji Lal Suman; five minutes. Before that, hon. Members, I have included the names of Shri Rajeev Shukla and Dr. M. Thambidurai in the Panel of Vice-Chairpersons to help the Chair, in addition to the earlier Panel. Shri Ramji Lal Suman.

THE UNION BUDGET, 2025-26– *Contd.*

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश) : सभापति जी, यह 2025-26 का जो बजट है, यह निराश करने वाला बजट है। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण अंचल की उपेक्षा हुई है। मनरेगा एकमात्र

योजना थी, जो ग्रामीण अंचल के श्रमिकों को काम देती थी। सभापति महोदय, 2021 और 2022 में मनरेगा का बजट 98 हज़ार करोड़ रुपए था, जिसे 2025-26 में घटाकर 86 हज़ार करोड़ रुपये कर दिया गया। सबसे अहम सवाल यह है कि मजदूरों ने जो पिछले वर्ष में काम किया था, तो पिछले वर्ष के 9,754 करोड़ रुपये मनरेगा के श्रमिकों का वेतन बाकी रह गया है।

सभापति महोदय, लोकसभा में एक समिति है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति, जिसके अध्यक्ष श्री सप्तगिरी शंकर उलाका हैं। उस कमेटी ने इस संबंध में रिकमंडेशन दी है। लोक सभा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि यह तो मिनी संसद है। इस कमेटी ने रिकमंड किया, सिफारिश की कि मनरेगा के श्रमिकों को जो वेतन मिलता है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए और महंगाई को आधार मानकर उनका वेतन सुनिश्चित होना चाहिए। सभापति महोदय, यह सरकार 5 किलो अनाज तो लोगों को दे रही है, लेकिन रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि 2022 और 2024 के बीच में 1 करोड़, 55 लाख श्रमिकों के नाम काट दिए गए हैं। इनके नाम काटने से पहले यह समीक्षा होनी चाहिए थी कि इनके नाम न काटने पड़ें और श्रमिकों को बराबर रोजगार मिलता रहे। सरकार ने संसद में एक जवाब में खुद स्वीकार किया है कि पिछले 10 वर्षों में 50 हज़ार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग बंद हुए हैं और 3,17,641 लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं।

सभापति महोदय, आज भारत सरकार पर 712 अरब डॉलर विदेशी कर्जा है और हिंदुस्तान में हर व्यक्ति पर 5 डॉलर, यानी 430 रुपये का कर्जा है। हमारे देश के पास जितनी विदेशी मुद्रा है, उससे ज्यादा विदेशी कर्जा हमारे ऊपर है और आज हम देश की प्रगति की बात कर रहे हैं! बजट का 20 प्रतिशत भाग तो जो विदेशी कर्जा है, उसके ब्याज में ही चला जाता है। अभी देश में 42 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। लोगों को रोजगार देने में कृषि का योगदान 18.2 प्रतिशत है। सभापति महोदय, कृषि का जो बजट है, वह केवल 4.8 प्रतिशत है। कृषि के संरक्षण और संवर्धन का जो काम हमारे देश में होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। 2024 के आकड़ों के अनुसार 127 देशों में से भूख के सवाल पर हम 105वें स्थान पर हैं।

सभापति महोदय, मैं यह निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश के 1 प्रतिशत लोगों के पास 44 प्रतिशत दौलत है। यह जो आर्थिक असंतुलन है, यही हिंसा को जन्म देता है। यह असमानता दूर होनी चाहिए। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि यह किसान विरोधी बजट है, नौजवानों के खिलाफ बजट है, ग्रामीण अंचल के खिलाफ बजट है और कुल मिलाकर आम जनता का इस बजट से कोई लेना-देना नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MILIND MURLI DEORA (Maharashtra): Mr. Chairman, Sir, I will, hopefully, complete within time. सर, भारत एक बहुत ही विविधता भरा देश है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की डिमांड्स बहुत अलग हैं। शहरी इलाकों में लोगों की बहुत सारी डिमांड्स हैं। एमएसएमईज़ की अलग डिमांड्स हैं। कृषि जगत में लोगों की अलग डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन्स हैं। मैं मानता हूं कि देश के किसी भी वित्त मंत्री को सभी कांस्टीट्युएंसीज़ को संतुष्ट रखना, उनको खुश करना बहुत ही कठिन है और एक प्रकार से असंभव है।

But, I would like to say that, genuinely, in my parliamentary tenure, very rarely have I seen a Budget where there is very little to add to, और इसलिए मैं माननीय वित्त

मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बजट के माध्यम से middle class से लेकर MSMEs तक सभी constituencies को खुश किया है।

सर, एक प्रकार से मैं वित्त मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसे बहुत सारे international, economic, political shocks आए, भारत ने उन shocks का सफलता से सामना किया। Whether it is the Covid pandemic, managing inflation, driving structural reforms like the PLI scheme, tax rationalisation and capital market deepening, the Finance Minister has demonstrated remarkable leadership and today, India's fiscal strength, our record Foreign Direct Investment inflows and booming digital economy stand as a testament to her execution capabilities.

(THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA) *in the Chair.)*

सर, मेरा मानना है कि आज एक प्रकार से इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण फोकस है, that is to make India and to make India's smaller companies export ready. For decades, Indian businesses have competed globally despite challenges like complex regulations and inadequate infrastructure. This Budget, in my opinion, changes the game completely. Number one, corporate tax कम करने से MSMEs को एक level playing field का अवसर दिया जाएगा। Number two, compliance का जो बोझ है, उस बोझ को घटाने से एक प्रकार से business-friendly environment अधिक मजबूत होगा। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में, जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, she spoke about many measures to deregulate inefficient regulations. I look forward to hearing from her in the months ahead on what the Finance Ministry plans to do. तीसरा, logistics और digital infrastructure में निवेश करके भारत ने 'Make in India' को 'Export from India' में बदल दिया।

सर, जब हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी बोल रहे थे, मैं actually गाड़ी में था और मैंने मोबाइल फोन पर उनका बजट के ऊपर भाषण सुना। चिदम्बरम जी ने कहा, सर, आपके पहले कहा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : अभी वे यहाँ नहीं हैं।

श्री मिलिंद मुरली देवरा : उन्होंने कहा कि budgets are about numbers, and he rightly said this. Budgets are about numbers. I spoke recently on the President's Address also. Therefore, I will be very brief today. I only want to highlight the unparalleled progress that India has seen in the last decade and I want to quote 14 numbers and 14 statistics.

Number one, in 2014, India's forex reserves were 304 billion dollars. In 2024, last year, India's forex reserves have reached 642 billion dollars, more than doubled. Ease of Doing Business ranking, which is very important, यदि हमें चीन के against, बाकी देशों के against compete करना है, तो Ease of Doing Business ranking is very important.

2014 में भारत की Ease of Doing Business ranking 142 थी, जबकि 2024 में भारत की Ease of Doing Business ranking 63 है। It has come down by more than half.

Regarding FDI in manufacturing, कुछ लोगों ने कहा कि PLI schemes are not working. Manufacturing में investment कहाँ आ रहा है! मैं उनका ध्यान इस statistics की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों में Foreign Direct Investment in manufacturing was 98 billion dollars. 2014 से लेकर 2024 तक Foreign Direct Investment in manufacturing is 165 billion dollars. Internet connections - 2014 में हमारे देश में केवल 25 करोड़ internet connections हुआ करते थे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 2024 में 97 crore internet connections are there, which is an increase of four times. मैं एक ही statistics को repeat कर रहा हूँ, जो मैंने पिछले भाषण में भी कहा। UPI transactions - दिसंबर 2016 में केवल एक महीने में 7 billion UPI transactions took place. In December 2024, just two months ago, in one month only, 17 billion UPI transactions took place across different platforms.

सर, परमाणु ऊर्जा क्षमता के बारे में जो आज वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार nuclear energy को unleash करना चाहती है, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। परमाणु ऊर्जा क्षमता 2014 में 4,780 मेगावाट थी, जबकि 2024 में यह 8,180 मेगावाट है।

In 2024, it went up to 8,180 MW. 2014 में मोबाइल फोन उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ केवल 2 factories हुआ करती थीं, लेकिन 2024 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल manufacturing देश बना है। अगर भारतीय exports देखें, तो 2013-14 में 466 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे, लेकिन 2023-24 में 777 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। Sir, medical colleges benefit the common persons. In 2014, there were 387 medical colleges, of which 7 were AIIMS. In 2024, there are 660 medical colleges, of which 23 are AIIMS. This is an increase of two times. As far as IITs and IIMs are concerned, in 2014, there were only 16 IITs and 13 IIMs while in 2024, we have 23 IITs and 21 IIMs in our country. जब हम infrastructure की बात करते हैं, the biggest statistics, in my opinion, is the airports. 10 साल पहले भारत में केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, जबकि 2024 में 157 एयरपोर्ट्स हमारे देश में हैं। This number has more than doubled.

जो multi-dimensional गरीबी है, वह 2013-14 में 29.17 परसेंट थी, जो 2022-23 में 11.2 परसेंट हो गई। अगर हम जन-धन खाते देखें, तो 2014 में केवल 15 करोड़ अकाउन्ट्स थे, जबकि 2024 में 50 करोड़ अकाउन्ट्स हो गए। It is an increase of more than three times. In 2014, the renewal energy capacity was 76 GW while in 2024, it went up to 203 GW, which, again, is an increase of three times. I welcome the former Finance Minister's remarks that Budgets are about numbers. These are the numbers which I have highlighted to show what progress has been made in the last ten years.

Sir, there is one last point which I would like to make and my friends from the Congress may correct me, if I am wrong. I think, in 1997, when Mr. Chidambaram, the then Finance Minister, presented his Budget speech, said, "The world does not

wait for those who hesitate." He also praised Dr. Manmohan Singh ji. मैंने भी President's Address पर बोलते हुए अपनी स्पीच में डा. मनमोहन सिंह जी की प्रशंसा की थी। To be fair to Dr. Singh, he never hesitated when UPA was in power nor was he in two minds or confused. But, unfortunately, there were elements in his Government who were hesitant about taking India forward. Because of that unfortunate thing, India lost a decade of progress. Today, one of the biggest reasons that India has progressed, has been progressing and is able to withstand the global shocks that the world is throwing at us, is the decisive leadership of the hon. Prime Minister, Narendra Modi ji, having no ambiguity that to make the country grow and to solve the problem of inequality, we have to have aggressive economic growth.

With these words, I once again praise the hon. Finance Minister for an outstanding Budget. Thank you very much.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : आपने समय से अपनी बात समाप्त की। आपने बहुत अच्छे शब्दों में पूरा विवरण दिया। धन्यवाद। Now, Shri Jose K Mani. You have five minutes.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, when it comes to the General Budget, we talk about the whole nation but, today, I am compelled to talk about my State, Kerala. I stand here to raise the voice of the people of the State of Kerala because the Budget has completely neglected the State of Kerala.

Sir, if you see the last eight Union Budgets, can any Member from the Treasury Benches point out one single project, one single assistance or one single scheme exclusively for the State of Kerala? Nothing has been done for the State of Kerala. Why, Sir? I am not asking for any special treatment for the State of Kerala. I am only asking for a fair treatment. Sir, as you know, Kerala is a shining example of growth in the field of education, healthcare, tourism and other aspects.

We have earned our place in the India's growth map. In the case of human development, we are much higher than some of the States in the country. But then, why are we being neglected? One of the State Ministers in the Central Ministries was commending Kerala and saying, if you want assistance, you must deteriorate the development and we will give you money. It is not that, but I will tell you the reason. The reason is that the BJP do not envisage any political gain in Kerala. Sir, out of Rs. 25 lakh crores for the allocation of all the States, Kerala has requested for Rs. 40,000 crores. But what has been given to Kerala? It is nil; it is zero.

Now, if you talk about Wayanad, devastating landslide took place there. It was there on the national TV, everywhere. It happened when the House was in Session. I remember, about 375 people lost their lives and thousands of people lost their

homes, their dear ones. The hon. Prime Minister visited Wayanad. Thank you for that. He visited the camps, caught hold of all the people inside the camp, got a little child, a boy of about 12 years, got close to him and said, "Don't worry. We will take care of all the people over here. We will give you assistance." And what has he given? What has he allotted? So many months have passed but not even a single pie has been allotted.

We have been talking about AIIMS. You know the nurses of Kerala. They are most sought after in the world. But we have been asking for AIIMS for the last 10 years, but deliberately, it is not being allowed; deliberately, it is not being sanctioned because there is no political gain for BJP in Kerala.

Now, I will talk about rubber. For the last ten years, I have been speaking about rubber in the Lok Sabha. Here also, I have been speaking about rubber. The Kerala economy revolves around the price of rubber. Ten years back, the rubber price was Rs.240 per kilo. Now, it has come down to Rs.140 per kilo, the lowest during many years. It is so because of uncontrolled import of natural rubber. Now, let it be that you are supporting or it is being done for the tyre manufacturers. Let it be like that. But why is the import duty on it? It is to protect the rubber growers, isn't it? During the last five years, the Government has earned about Rs.5000 crores on the import duty. That import duty is not the revenue of the Central Government. It is the sweat and toil of the farmers of Kerala because 75 per cent of the production is from Kerala. We have a scheme in Kerala, Sir. It is a beautiful scheme, maybe one of the best in Kerala. Under this scheme, the minimum support price of rubber is Rs.180. If the price goes below Rs.180, they will compensate. So, I request the Government of India to give 75 per cent of the money to the Rubber Production Incentive Scheme. One more thing is about the NRIs.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : माननीय सदस्य, कृपया आप conclude कीजिए।

SHRI JOSE K. MANI: Just one last point, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): चूँकि आपका समय पूरा हो गया, इसलिए आप conclude कीजिए।

SHRI JOSE K. MANI: India received an estimate of Rs.129 billion worth of remittance, the highest ever in the country in years. (*Time-bell rings.*) But the Budget is a slap on the Non-Resident Indians all over the world by introducing an oppressive tax regime on NRIs under the guise of global financial transparency. (*Time-bell rings.*)

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी बात आ गई है।

SHRI JOSE K. MANI: If you look at Kerala, it is a slap by the Centre to Kerala because there is no political gain. It is unfair.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका समय पूरा हो गया, इसलिए आप अपनी बात को पूरा कीजिए।

SHRI JOSE K. MANI: Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. DINESH SHARMA): The next speaker is Shri Birendra Prasad Baishya. Ten minutes.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (ASSAM): Thank you, Vice-Chairman, Sir, for allowing me to speak on the Union Budget. I rise here to speak on the Budget on behalf of my Party, Asom Gana Parishad, and on behalf of our Party President, Mr. Atul Bora.

5.00 P.M.

Sir, this Budget is for the economic growth of the country. This Budget is a farmer-friendly Budget. This Budget is for the poor and the middle-class people of our country. I am delighted to say that the Budget is also for the development of the North-Eastern Region of our country, including Assam.

Sir, for development, four engines are required. These are: agriculture sector, MSME sector, investment sector and export sector. Our Government has given topmost priority to our agriculture sector. It includes farmers' welfare and increasing the income of the farmers of our country. This Budget is a very good Budget. People in every part of the country say that this Budget is for the poor people and the middle-class people of our country. In her Budget speech, our Finance Minister has given tax holiday for up to 12 lakh rupees. It will be helpful for the middle-class people and the poor people of our country. This is possible only because our Prime Minister, Shri Narendra Modi, is here. This is possible only because *Modi hai to mumkin hai*.

Sir, this Budget has given more for capital expenditure and development. The Government is going to invest more than Rs.11.21 lakh crore for capital expenditure, which is three per cent of our GDP. Capital expenditure means there will be creation

of new airports, new railway lines, new industries and new ports. It means money will be coming in the market in a big way. It means capital expenditure is going to expand in our country. It will help in job creation in our country. I must compliment hon. Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman. I would also like to compliment our hon. Prime Minister for his wonderful guidance. This Budget is a historic Budget for the North-Eastern Region.

In the Budget proposal, the Railway Minister has proposed to invest about Rs.11,000 crore for the infrastructure development and to improve railway connectivity in the North-Eastern Region. Redevelopment of 92 railway stations will be done as part of the Amrit Bharat Station scheme and the entire Assam railway network will be covered by electricity. This is a historic announcement by the Railway Minister. I welcome it. For the first time, the Railway Minister is going to spend about Rs.11,000 crore for the development of the North-Eastern Region. For more than 40 years, we have been fighting for electrification in the Railways.The Railway Minister has announced that by 2025 all the railway tracks will be connected with electricity.

With due respect to our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh *ji*, I would like to say one thing. Dr. Singh was a great economist. He was from Assam. Our Fertilizer Minister was from Assam. For more than 30-40 years, we have been saying about Namrup fertiliser plant. Can you imagine this fertiliser company was there in the 60s? Now, this Budget has given proposal to set up urea production in our State. There will be urea industry in Namrup which is going to produce 12.7 lakh metric tonne urea annually.

It is a historic decision because fertilizers have played a very important role in the socio-economic development of Assam and the North-Eastern region. Fertilizers have played a very important role for the tea growing industry of our country. But, for the last several years, we had been fighting and we were not getting justice. There was nobody to look after us; nobody was working for us. I am grateful to the hon. Prime Minister of the country who took this initiative; there will be a urea production unit in India which is going to produce 12.7 lakh metric tonne urea annually. In this regard, I would like to say a simple sentence expressed by the hon. Chief Minister of Assam because in this project Assam Government is going to invest 40 per cent share. I must compliment the hon. Chief Minister of Assam for his courageous and active support to this project which will create new industrial development in the country. Dr. Himanta Biswa Sarma said that after the upcoming semiconductor plant in Jagiroad in the State, the new urea production facility will be a 'game-changer for the entire North-East' and described the day as 'historic for Assam'. Yes, Sir, this is a historic decision for Assam because this will be a game-changer for the

development of our North-Eastern region. We will go towards 'Atmanirbhar Bharat' in urea production with this project. For this, we will get market from the South-East Asia, Bangladesh and other countries. So, I am grateful.

Sir, I would like to mention one more thing. The Assam Government took up an ambitious plan to attract investors in the North-Eastern region. This is Advantage Assam 2.0. I am very, very happy to say that many prominent industrialists from many countries of the world including Japan, Korea and nearby countries already have accepted to participate in Advantage Assam 2.0 in 2025 which will be organized in Guwahati during February 25-26. I must compliment the hon. Chief Minister of Assam. This will be a new era. This will start a new history for the economic development of Assam. After successful organization of Advantage Assam 2.0, Assam will be one of the major industrial players of our country.

Sir, I am very proud that I belong to a tea producing State of Assam. We produce tea. Assam tea has international name which earns a lot of foreign exchange, is helpful and a boost for our economy. In our economy, small tea growers play a very, very important role because they are self-employed. I humbly request the Government. We are getting all possible support from the Government for looking after the small tea growers of our country. They are self-made, self-employed and if they get some justice and help from the Government of India, our tea industry will go better. Our small tea growers play a very important role. Again, I salute Nirmala Sitharamanji and the hon. Prime Minister for giving income tax relief up to an income of Rs.12 lakh to the people of Assam which will be helpful to the poor people, middle-class people, etc. It means that our Government, Narendra Modi Government, is for the poor people.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : अब आप conclude कीजिए।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA : It is for the economically backward people and it is for the middle class people. With this, I totally support the Budget and compliment our hon. Prime Minister. Thank you very much for giving me this opportunity.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : नेक्स्ट स्पीकर, डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी। आपके बोलने का समय 20 मिनट है।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर, बजट पर चर्चा करने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए

मौका दिया। मेरे भाषण के शुरू में मैं सर्वप्रथम दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के लिए सबको बधाई देती हूं। यह कार्यकर्ता और जनता का जो विश्वास है, उसको मोदी जी ने हासिल किया, इसलिए केन्द्र में जो काम चल रहा है, वही दिल्ली में हो सके, इसलिए डबल इंजन की सरकार को उन्होंने चुना है। व्हाट्सएप पर बहुत सारे वायरल्स आ रहे थे कि लोगों ने आखिर शीशमहल में रहने वालों को आईना दिखा ही दिया। पूर्व मुख्य मंत्री कह रहे थे कि मोदी जी मुझे कभी हरा नहीं सकते, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि सरकार तो गिर गई, सरकार तो हार ही गई, लेकिन खुद की सीट भी नहीं बचा सके। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि चींटी को मारने के लिए हथौड़े की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी ऐतिहासिक हार उनकी हुई है और उनको आईना दिखाने के लिए दिल्ली वालों का बहुत-बहुत आभार। इससे पहले महाराष्ट्र ने ऐसी ही बड़ी होश उड़ाने वाली जीत हासिल की थी, तो महाराष्ट्र भी अभिनन्दन का पात्र है। हरियाणा ने शुरुआत की थी, तो हरियाणा ने एक श्रृंखला, एक कड़ी की शुरुआत की और इसमें बाद में महाराष्ट्र और दिल्ली आगे बढ़ते गए। आने वाले चुनावों में बाकी राज्य भी इस कड़ी में जुड़ते जाएंगे, यह मेरा विश्वास है। मैं 2025-26 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर बात रखूंगी ही, लेकिन उसके पहले मैं एक हिसाब चुकता करना चाहती हूं। इस वर्ष के अंदाजपत्र के शुरू में बजट सादर होने के पहले आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत ही प्रेरणादायी भाषण किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत एक ऊंची उड़ान ले सकता है। यह उड़ान कैसी होगी, इसके बारे में उन्होंने संकल्प चित्र रखा। विकसित भारत की यात्रा में कोई छूटने न पाए, इस ध्येय अनुरूप यह सरकार काम करेगी, यह एजेंडा उन्होंने बताया। सच्चा राष्ट्रवाद, केवल भारत की भौतिक एकता नहीं, सांस्कृतिक एकता का मजबूतीकरण भी होना चाहिए। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह वाक्य उन्होंने उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र में अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन इन सबमें हमारी पहचान एक है और वह है भारत और इस भारत का एक ही संकल्प है और वह है विकसित भारत। इनके प्रेरणादायी वाक्यों ने मुझे तो रोमांचित कर दिया। पिछले साल का मुझे याद है, जब मैं नई-नई सांसद बनी थी, तो उनका पहला ही अभिभाषण था। उन्होंने जो अभिभाषण के अंत में कहा, वह वाक्य इतना अच्छा है, इतना गहरा है, तो मैं आपके लिए उसको एक बार दोहराना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि यह सदी भारत की सदी है और इस सदी की पीढ़ी का योगदान आने वाले हजार साल याद रखेंगे। ये वाक्य उन्होंने कहे थे, जो मेरे मन में बस गए हैं। जहां-जहां मुझे मौका मिलता है, वहां मैं इन वाक्यों को लोगों को जागृत करने के लिए उद्धृत करती हूं। मैं लोगों को यह बताने के लिए कि आओ, चलो, इस सदी की पीढ़ी के लोग कुछ ऐसा करें कि आने वाले हजार साल भारत की तरफ कोई भी वक्रदृष्टि से देख नहीं पाएगा, ऐसा काम करके जाएं। इतना गहरा यह वाक्य है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो भाषण मुझे प्रेरित करता है, बाकी जो अनेक राष्ट्रभक्त लोग थे, उनको भी प्रेरित करता है, तो वह किसी को बोर कैसे कर सकता है? सर, मैं एक अध्यापक हूं। मुझे मालूम है कि कुछ-कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी दिमागी हालत होती है, बौद्धिक क्षमता कुछ ऐसी होती है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनका concentration भी नहीं होता है, उनका ध्यान नहीं लगता है, कभी-कभी वे बोर हो जाते हैं और कभी-कभी सो भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि किरेन रिजिजु जी के भाषण के समय वे बहुत गहरी नींद में थे कि कोई उनको उठा रहा था, वह भी उनको पता नहीं चल रहा था।

महोदय, ऐसी बात करने वाले कभी-कभी जागते हैं और जागने के बाद क्या बात करते हैं? वे यह बात करते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है, भारत की राष्ट्र संस्था के साथ हमारी लड़ाई है, भारत की राज्य संस्था के साथ हमारी लड़ाई है। मतलब, ये अपने ही राष्ट्र से लड़ेंगे। जब वे जागते हैं, तब £ की ऐसी भाषा बोलते हैं। मुझे दुख भी होता है, दर्द भी होता है और शॉक भी लगता है। जैसे हमें शॉक लगा कि वे एक सांसद होकर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं ...(**व्यवधान**)... यह भी वही विषय है, बजट का एजेंडा है, मैं आपको उत्तर नहीं दूंगी, क्योंकि आपका एजेंडा अलग है। ...(**व्यवधान**)... यह राष्ट्रभक्ति पर समर्पित बजट है, यह राष्ट्र को समर्पित बजट है। जिनका mind £ है, उन्हें यह बजट निराशाजनक लगेगा, लेकिन जैसे हम शॉक में चले गए, वैसी ही एक घटना बताना चाहती हूं। महोदय, हमारे बिहार के एक सामान्य नागरिक हैं – मुकेश चौधरी जी। कदाचित् आपने भी यह न्यूज सुनी होगी, लेकिन जब उन्होंने यह न्यूज सुनी कि माननीय 'xyz' ने ऐसा £ विधान किया है, तो उनके हाथ में दूध की एक बोतल थी, वह बोतल हाथ से गिर गई और उनका दूध waste हो गया। वे दौड़े-दौड़े कोर्ट में गए और उन्होंने मुकदमा चलाना चाहा कि मेरा भी नुकसान हुआ है, मेरे देश का भी नुकसान हुआ है और ऐसे £ यहाँ नहीं होने चाहिए। मतलब, इनकी बातों से लोगों का दिमाग खराब होता है, उन्हें शॉक लगता है, उन्हें दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन इन्हें राष्ट्रभक्ति के भाषण से बोरियत होती है और ये बाहर जाकर लोगों से बात करते हैं कि poor thing. आप poor thing किसे बोलते हैं? आप भारतीय नारी का अपमान करते हैं। ...(**व्यवधान**)... वे एक उच्च पद पर आसीन हैं। ...(**व्यवधान**)... आप वह छोड़ दीजिए। दिल्ली के चुनाव ने यह बता दिया है कि अगर कोई भी भारतीय नारी का अपमान करेगा, तो एक श्राप लगेगा ही लगेगा। ...(**व्यवधान**)... भारतीय नारी के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोलने वाले लोगों को आने वाले समय में और भी बोर होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें किसी भी राज्य में सत्ता नहीं मिलेगी, उनके मेम्बर्स चुनकर नहीं आएंगे और जब घर में बैठने की नौबत आएगी, तो उनके लिए वह समय और भी बोर होने वाला है। जब ऐसा होगा, तब उन्हें पता चलेगा कि असली poor thing क्या होती है। चलिए, छोड़िए, मैं बजट पर बात करती हूं, लेकिन आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... मैं मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस सरकार और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि उन्होंने आठवीं बार यहाँ पर अपना बजट सादर किया है। यह बजट सर्वकक्ष और सर्वसमावेशी है, इसलिए उनका बहुत-बहुत अभिनंदन।

महोदय, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि यह हर भारतीय के सपनों को साकार करने वाला बजट है, यह हर भारतीय नागरिक का तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण करने वाला बजट है। महोदय, आदरणीय निर्मला जी ने भी कहा था, A country is not just its soil, a country is made up of its people. इससे अटल जी की कविता याद आती है कि भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता-जागता राष्ट्रपुरुष है, हम जिएंगे तो इसके लिए, और मरेंगे तो इसके लिए। यह इस राष्ट्रपुरुष को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला बजट है। इस बजट का संकल्प क्या है? महोदय, इस बजट का संकल्प विकसित भारत है। इसको कब तक विकसित भारत बनाना है? इसको 2047 तक विकसित भारत बनाना है। कैसे बनेगा विकसित भारत? यह सबका विकास करके विकसित भारत बनेगा। सबका विकास कैसे होगा? महोदय, reform,

£ Expunged as ordered by the Chair.

perform and transform से सबका विकास होगा। महोदय, रिफॉर्म्स कैसे होंगे? इसके लिए चार growth engines या आप चार pillars भी बोल सकते हैं, उन्हें identify किया गया है। ये चार पिलर्स कृषि, MSME, investment और निर्यात हैं। महोदय, कितने अच्छे तरीके से विचार करने के बाद बजट तैयार किया गया है कि किसको strong बनाएंगे और कौन-सी पटरी पर हमारा देश चलेगा। महोदय, इसके लिए चार ग्रोथ engines बनाए गए हैं।

सबसे वीकर — हम वीकर क्यों बोलें? अगर उन्हें स्ट्रॉंग किया जाएगा, तो देश स्ट्रॉंग हो सकता है। उन्होंने ऐसे चार घटक चुने हैं, जिनमें अन्नदाता, युवा, नारी और गरीब हैं। इसके सिद्धांत क्या हैं — उन्होंने कहा कि गरीबी से मुक्ति - यह सिद्धांत है। अच्छे स्तर की शिक्षा - यह एजेंडा है। सस्ती, बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था - यह एजेंडा है। शत-प्रतिशत कुशल कामगार और सार्थक रोजगार — यह थीम है। आर्थिक गतिविधियों में 70 प्रतिशत महिलाएं समाविष्ट हों - यह थीम है। हमारा देश फूड बास्केट ऑफ दि वर्ल्ड बने, इसके लिए किसानों को सक्षम करना चाहिए - यह थीम है। डेवलपमेंट में तेजी, मध्यम वर्ग की क्षमता को बढ़ाने में मदद, समावेशी इन्क्लूसिव डेवलपमेंट, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना और परिवारों के मनोबल को उल्लसित करना, मतलब इतने अच्छे थीम पर कोई भी योजना हो, कोई भी बजट डाला हो, कोई भी प्रावधान हो, सबके लिए यह थीम है कि इससे क्या होने वाला है। अब, मध्यमवर्ग का उल्लेख किया है, तो मध्यमवर्ग के बजट को, उनके बर्डन को कम करने के लिए 12 लाख तक की आय पर पूरे तरीके से टैक्स फ्री कर दिया है। जो जॉब करते हैं और उनकी सेलेरी आती है, उन्हें 12,75,000 के ऊपर टैक्स नहीं होगा। आप तुलना कर सकते हैं। अगर हम 2014 की बात करें, तो 2014 में आपकी आय आठ लाख होती, तो आपको 90,000 टैक्स देना पड़ता था, अगर आपकी आमदनी 12 लाख होती, तो दो लाख का टैक्स देना पड़ता था, अगर 24 लाख की आमदनी होती, तो 2.06 लाख टैक्स देना पड़ता, लेकिन सामान्य नागरिक की इस टैक्स की रकम की बचत हो चुकी है, इसलिए उनके लिए ये प्रावधान, ये घोषणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदा देने वाली हैं। हालांकि, हम दूसरों से तुलना क्यों करें। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही यह सरकार खुद से ही स्पर्धा करती है। पिछले साल हमने क्या किया था, उससे आगे जाकर हम क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं, अपनी ही पूँजी बढ़ाने का काम यह सरकार करती है। मैं आपको एक और तुलना बताती हूँ। अगर 2024 में आपकी इनकम आठ लाख रुपये होती, तो 30,000 टैक्स भरना पड़ता। अगर आपकी इनकम 12 लाख होती, तो 80,000 टैक्स देना पड़ता और आपकी इनकम 24 लाख है, तो 1,10,000 इनकम टैक्स देना पड़ता, लेकिन अब इसमें बचत हो गई है, तो सर्वसामान्य नागरिक, जो मध्यमवर्गीय है, वह बहुत खुश है। कर सुधार के लिए और भी नए तरीके और भी एक सरल बिल आने वाला है, जो लोगों को अच्छा लगेगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं में से टैक्स हटा दिया है। सीनियर citizens के लिए सुविधा रहे, उनके ब्जाय पर टैक्स न लगे, इसका निर्णय किया गया है। किराया लेने वाले मकान मालिक के लिए निर्णय लिया गया है। सभी डिपार्टमेंट में बहुत सारी निधि का प्रावधान किया है। हम comparison कर सकते हैं कि 2013 में कितना बजट आता था और 2025 में कितना बजट आ रहा है। इस साल का डिफेंस का बजट 4,90,000 है। रूरल डेवलपमेंट का 2,66,000 है, होम अफेयर्स का 2,33,000 है। मैं सभी आंकड़े गिनवा सकती हूँ। आवासन का बजट 96,077 करोड़ रुपये है। ये सब आंकड़ें करोड़ में हैं। सड़क का बजट है — 2.87

लाख करोड़। अगर देखा जाए, तो 2013 में यह बजट 31,000 करोड़ था और अब यह बढ़कर 2.87 करोड़ हो गया है, मतलब यह बजट कई गुना बढ़ा है।

(THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA) *in the Chair*.)

इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। हम जहाँ-जहाँ भी जाएं, सभी जगहों पर बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं। इतने साल में ये इसे कर नहीं सके, लेकिन हमारी सरकार ने यह करके दिखाया है। रेलवे का बजट हो, स्टील का बजट हो, सभी में अच्छी तरह से आवंटन किया गया है। मैं महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा बात करना चाहूँगी। जब पिछली बार महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले थे, हुए नहीं थे, तब महाराष्ट्र को बजट दिया गया। सबने बोला कि महाराष्ट्र के चुनाव हैं, तो महाराष्ट्र को बजट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस साल भी हमें बहुत अच्छी तरह से बजट मिला है।

पुणे मेट्रो के लिए 837 करोड़, मुम्बई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 1,400 करोड़, मुला-मुथा नदी संरक्षण प्रोजेक्ट के लिए 230 करोड़, नाग नदी सुधार परियोजना के लिए 295 करोड़, मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए 4,000 करोड़, हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के लिए 126 करोड़, मुंबई मेट्रो के लिए 1,600 करोड़, ग्रामीण सुधार के लिए 683 करोड़ रुपये मिले। अगर मैं इतना सब यहां गिनाऊंगी, तो बोलने वाला भी थकेगा और सुनने वाला भी थकेगा कि इतना बजट दिया है। मैं कम्पैरिजन करना चाहती हूं। मैं पुणे से आती हूं। जब तक केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, तब तक पुणे में, महाराष्ट्र में एक भी काम केंद्र की योजना से नहीं हो पाया था। आज यह स्थिति है कि पुणे में हर जगह मैट्रो का नेटवर्क बन रहा है। आज भी मैंने पुणे मैट्रो के बारे में पढ़ा कि उसे 800 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है। पुणे में नदी सुधार का प्रोजेक्ट चल रहा है, पुणे में सड़कें बन रही हैं। अभी धनंजय जी ने आलंदी का जिक्र किया था कि आलंदी से पंढरपुर तक और देहू से पंढरपुर तक वारी जाती है, तो वारी का जो मार्ग है, वह बहुत अच्छा मार्ग है, यह कार्य वारकरी संप्रदाय के लिए केंद्र द्वारा किया गया है, चाहे रिंग रोड हो, एसटीपी प्लांट्स हो, सभी के लिए इतना अच्छा बजट दिया है। मोदी जी की सरकार इस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

आज दुनिया में मोबाइल बनाने में भारत देश नंबर वन पर है। डिफेंस में 10 गुना एक्सपोर्ट बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसिंग देश भारत है। हर दिन दो कॉलेजेस बन रहे हैं। हर दिन 37 नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं। भारत मत्स्य निर्यात में विश्व में दो नंबर पर है। इसके अलावा भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे आवास योजना है, स्टार्टअप्स है, आयुष्यमान भारत है, अन्न सुरक्षा योजना है, जल जीवन मिशन है। इसी प्रकार एयरपोर्ट्स की संख्या 157 हो गई, अन्य 120 डेस्टिनेशंस होने जा रहे हैं, आईआईटीज़ हैं, पीएम रिसर्च फैलोशिप में छात्रों को 10 हज़ार फैलोशिप्स दी जाएंगी। इतने आंकड़े गिनाने के बाद भी ये बोलेंगे कि कुछ कर नहीं सकते हैं और स्टेटिस्टिक्स यह नहीं बता रहा है, वह नहीं बता रहा है। मतलब जैसे कुत्ते की दुम होती, वैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी करो, उनको कुछ भी बताओ, सिद्ध करो, आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन फिर भी वे नहीं मानेंगे। टीका-टिप्पणी करना उनकी फितरत में है। कभी चुनाव पर बोलेंगे, कभी ईवीएम पर बोलेंगे, कभी संविधान पर बोलेंगे, कभी वोटर्स रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, इस पर

बोलेंगे, कभी धार्मिक विषयों पर बोलेंगे। इन्होंने तो कुम्भ तक को नहीं छोड़ा। सर, मेरी विनती है कि कृपया मेरा समय थोड़ा सा बढ़ा दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : समय तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपकी पार्टी ने आपको जो टाइम दिया, यह उसी के हिसाब से है। आपके पास 1 मिनट और 37 सेकंड का समय बाकी है। मैडम, आपने जो कुत्ते वगैरह बोला है, तो यह बाद में देखना पड़ेगा कि वह अलाउड है या नहीं। आप बोलिए।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : सर, मैंने एक एनिमल के बारे में बोला। मैंने किसी आदमी के बारे में नहीं बोला।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : आपने लोगों की तुलना तो एनिमल से की है।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : सर, यह मुहावरा है। जब स्वतंत्रता के बाद का पहला कुम्भ था, तब के माननीय प्रधान मंत्री नेहरू जी वहां गए थे और उनके जाने के बाद वहां जो भगदड़ हुई, तो उस पर ये राजनीति नहीं करेंगे। ...**(व्यवधान)**... लेकिन आज अगर कोई दुर्घटना घटी है ...**(व्यवधान)**... मैं 2003 की बात करती हूं। नासिक में कुम्भ हुआ था। नासिक के कुम्भ में कालाराम मंदिर के सामने दक्षिण द्वार पर भगदड़ हुई थी और बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। 2013 में मॉरीशस के प्रधान मंत्री आए थे और गंदगी देखकर रोते-रोते वापस चले गए कि अरे, क्या यह गंगा है, ऐसी गंगा तो मैंने कभी सोची नहीं थी! इस तरह से तब कुम्भ का आयोजन किया गया था। तब कुम्भ का आयोजन किसने किया था? आजम खान जी को यह जिम्मेदारी 2013 में उस वक्त के मुख्य मंत्री जी ने दी थी। उस वक्त के मुख्य मंत्री जी ने अब इस साल वहां कुम्भ में जाकर डुबकी लगाई। जब उत्तर प्रदेश की सारी टीम जाती है, वहां के सब मिनिस्टर्स जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और फोटो निकालते हैं, तब बोलते हैं कि आलोचना होती है। अरे, फोटो निकालने की क्या जरूरत है, आप पब्लिसिटी करते हैं। ...**(समय की घंटी)**... लेकिन जब वे खुद जाएँगे, विपक्षी दलों के भी सारे लोग वहाँ जाकर आए, उन्होंने फोटो निकाली, फिर भी वे आलोचना करते हैं, तब उनको नहीं लगता कि टीका करनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : धन्यवाद, मैडम। श्री अखिलेश प्रसाद सिंह।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : सर, मुझे एक मिनट और दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : ठीक है, मैडम, आप 30 सेकंड में conclude करिए।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : सर, मैं केवल एक आवाहन करना चाहती हूँ कि राजनीति को छोड़ दीजिए। विकसित भारत की यात्रा में कोई छूटने न पाए, यही तो एजेंडा है। आप भी इससे अलग मत जाइए, आप भी इस विकसित यात्रा में आइए, इस बजट का समर्थन कीजिए और आने वाले

समय में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लेकर जाना है, तो उसके लिए जो भी तरीके, जो भी योजनाएँ लाई जाएँ, ताकि अच्छी अर्थव्यवस्था हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसमें शामिल हो जाइए, मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : आपने कुंभ की मौत का जो 800 का आँकड़ा बताया था, उसको आज आप authenticate करके, लिख कर टेबल ऑफिस को दे दीजिएगा।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी : हाँ, हाँ, बिल्कुल।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : ठीक है। श्री अखिलेश प्रसाद सिंह।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार) : महोदय, आपने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए यह खुशकिस्मती है कि आपके जैसा विद्वान आदमी चेयर पर बैठा है और मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया गया।

महोदय, वित्त मंत्री जी का इस बार का जो बजट भाषण था, उसको मीडिया में और सब जगह ऐसे पेश किया गया, जैसे बिहार को बहुत बड़ी सौगात मिली है। संजय कुमार झा जी उधर से मुस्करा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की सौगात वे बहुत बार देख चुके हैं। यह मेरे लिए गौरव की बात है कि बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री और देश की सरकार में अभी मंत्री के रूप में काम कर रहे आदरणीय जीतन राम माँझी जी भी इस सदन में मौजूद हैं। मैं बिहार के दुख-दर्द को उनसे साझा करना चाहता हूँ। बिहार क्या था और बिहार किस तरह से systematically neglect हुआ है, मैं आपके माध्यम से यहाँ उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। महोदय, 2000 में मैं बिहार विधान सभा का सदस्य था और उसी समय बिहार का बँटवारा हुआ था। Reorganization Bill पर जब देश की संसद में बहस हो रही थी, तब उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, एल.के. आडवाणी जी, जो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं, उन्होंने बिहार के बँटवारे पर चर्चा करते हुए बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही थी और बिहार को 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने की बात की थी। आज भी बिहार के लोग उस पैकेज की बाट जोह रहे हैं कि वह पैकेज कहाँ गया! उसके बाद बिहार के संदर्भ में systematic तरीके से जो कुछ हुआ, मैं उसकी चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। पिछले दो-तीन साल से हम लोग लगातार वित्त मंत्री जी की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात सुनते आ रहे हैं। हम सब लोगों की भी यही इच्छा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, जो सबसे जरूरी काम है। आर्थिक विकास की दृष्टि से देश में जो regional imbalance है, देश में जो क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति है, उसको जब तक address नहीं किया जाएगा, या जब तक उसका कोई विज़न नहीं रखा जाएगा, तब तक यह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं खड़ा हो सकता है। महोदय, पिछले 60 सालों में क्षेत्रीय असंतुलन की दृष्टि से बिहार की जो स्थिति हुई है, वह अपने आप में बेहद चिंताजनक है। कहीं और की रिपोर्ट होती, तो आप लोग भी उसको मानने से सीधे तौर पर इनकार कर देते, लेकिन खुद प्रधान मंत्री जी की जो Economic Advisory Council है, ये तो उसी की रिपोर्ट के आंकड़े हैं और मैं उसी से क्वोट करना चाहता हूं।

महोदय, 1960-61 में बिहार में per capita income national average का 70 परसेंट हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में बिहार का per capita income national average का लगभग 32 परसेंट रह गया है। यानी अगर national average 100 रुपये है, तो बिहार की per capita income केवल 32 रुपये है। इतना ही नहीं, 1960-61 में देश के कुल जीडीपी में बिहार का योगदान लगभग 8 परसेंट था, जो आज मोदी जी की रिजीम में घटकर 4 परसेंट रह गया है। बिहार में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की क्या स्थिति है, इसके लिए भी मैं कुछ स्पेसिफिक डेटा सदन में रखना चाहता हूं। बिहार में सड़कों पर per capita खर्च केवल 44 रुपये है, जबकि national average 117 रुपए है। इसी तरह से सिंचाई पर बिहार में per capita खर्च केवल 104 रुपए है, जबकि national average 199 रुपए है। नाबार्ड ने खुद अपनी एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि बिहार में देश के बाकी राज्यों के मुकाबले agricultural loan का जो disbursement है, वह काफी कम है, यानी देश की लगभग 9-10 परसेंट आबादी वाला जो राज्य है, वह अगर आर्थिक विकास के सभी parameters पर इतना पीछे है, तो ऐसे में आप देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कैसे कर सकते हैं और कौन इस पर विश्वास कर सकता है?

महोदय, केवल यही नहीं, अगर आप नीति आयोग की पिछली तिमाही की या पिछले 6 महीनों की रिपोर्ट देख लें, तो देश में जो 28 बड़े राज्य हैं, उनमें प्रायः सभी मानकों पर, चाहे वहां की स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा व्यवस्था हो और औद्योगिकीकरण के मामले में बिहार प्रायः या तो 28वें स्थान पर और नहीं तो 27वें स्थान पर चला गया है। मैं इन आंकड़ों के आधार पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि बिहार का विकास इस सरकार की प्राथमिकता में कहीं भी नहीं है। जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बिहार ने पहले आपको 32 सांसद दिये, उसके बाद 2019 में आपको 39 सांसद दिए, इस बार यह आंकड़ा थोड़ा घटा है और इस बार आपको 30 सांसद दिये हैं। सर, एक तो मैंने आपको बिहार के बंटवारे के समय की बात बात बताई। 2015 में जब आदरणीय नीतीश जी अलग थे, उस समय भी किस तरह से प्रधान मंत्री जी ने बिहार की बोली लगाई थी, उसे बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार के भिन्न-भिन्न दलों के कई सांसद यहां बैठे हुए हैं। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ और अंत में 1,25,000 करोड़ की घोषणा हुई। ठीक दूसरे दिन बिहार के मुख्य मंत्री आदरणीय नीतीश जी का एक इश्तहार अखबार में आता है और उसमें 1,25,000 करोड़ में से केवल 17,000 करोड़ के एक नये पैकेज की घोषणा थी, बाकी जो पुरानी योजनाएं थीं, उन्हीं को पैकेज में घोषणा के रूप में घोषित किया गया था। ...**(व्यवधान)**... नित्या बाबू, आप अपनी नौकरी बचाइए। कुछ-कुछ सही बातें भी सुननी चाहिए, तभी जाकर कुछ कर सकते हैं। पहले भी यहाँ पर बिहार से मंत्री थे, हम लोग भी मंत्री थे, लेकिन उस समय लगता था कि दिल्ली की सरकार में एक धमक थी, एक हनक थी। आज तो कोई जानता ही नहीं कि वहाँ से कौन-कौन मंत्री हैं। मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहता हूं। मैं आपको कोई ऐसी-वैसी बात नहीं कहूँगा, जिसमें सच्चाई नहीं हो। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : नित्या बाबू, आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): He is not yielding.

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : लंबा अरसा हो गया। **...(व्यवधान)...** आप भी वर्ष 2000 की उसी विधान सभा में थे। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : माइक इनका ऑन है। **...(व्यवधान)...**

SHRI AKHILESH PRASAD SINGH: Sir, I am not yielding.

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : माइक इनका ऑन है। **...(व्यवधान)...**

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : इसके बाद उनको मौका दे दीजिएगा। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): He can speak. ***...(Interruptions)...*** उनको नहीं बोलना है, माइक इनका ऑन है। आप बोलिए।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : यह systematic neglect है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस बजट में बिहार के बारे में फिर एक घोषणा की गई कि वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का नेशनल इंस्टिट्यूट खोला जाएगा - यह बहुत अच्छी बात है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। आप जहां से आते हैं, वहां केले की बहुत अच्छी खेती होती है। वहाँ क्वालिटी बनाना का उत्पादन होता है, लेकिन मखाना आयोग तो बनेगा, बनाना आयोग कब बनेगा? वहीं आपके बगल में इतना बढ़िया लीची का उत्पादन होता है, इसलिए आप लीची आयोग भी बनवाइए, ताकि उसको भी इसका फायदा मिले। लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है, वह पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना है। पिछली सरकार से, उस समय भी पारस जी फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर थे, वे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई थे और अभी उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी उसी विभाग के मंत्री हैं। बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है - इसके लिए भी मैं एक-दो आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसे सुन कर आपका सिर शर्म से झुकना चाहिए कि बिहार के साथ क्या हो रहा है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : कृपया आप सुनिए। **...(व्यवधान)...** जब आपका नंबर आएगा, तब आप भी जवाब दीजिएगा।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : महोदय, लोक सभा में 11 अगस्त, 2023 को एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्रालय ने जो आंकड़ा दिया, उसके अनुसार बिहार में कोल्ड स्टोरेज की कुल

संख्या 313 है, जबकि अकेले गुजरात में 1,000 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज है और उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की संख्या लगभग 2,500 है। आप एक तरफ तो लंबी-लंबी घोषणाएं करते हैं, दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है, वह यह है। आप उसमें जितना पैसा दे रहे हैं, मैं बिहार के संदर्भ में उसके लिए भी एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए राज्यों को जो आर्थिक मदद देता है, उसमें बिहार को वर्ष 2021-22 में 33 करोड़ रुपए मिले, वर्ष 2022-23 में फिर से 33 करोड़ रुपए मिले और वर्ष 2023-24 में यह राशि घट कर 32 करोड़ रुपए हो गई। यह तो है आपकी कथनी और करनी में फर्क। इसको समझना चाहिए।

अब देखते हैं कि आप लोगों ने पहले जो घोषणाएं की हैं, उनकी क्या स्थिति है। आदरणीय रवि शंकर प्रसाद जी जब आईटी मिनिस्टर थे, तब उन्होंने बड़े जोर-शोर से कहा था कि बिहार में बेंगलुरु और हैदराबाद की तरह आईटी पार्क स्थापित करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर खोले जाएंगे। 10 साल बीत गए, लेकिन मेरे ख्याल में एक कॉल सेंटर भी बिहार में स्थापित नहीं हुआ।

अब चीनी मिल की बात कर लेते हैं। यहीं 1960, 1961, 1962 में, उस समय आदरणीय माँझी जी कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, यही बिहार में 27 परसेंट चीनी बिहार नेशनल किटी में देने का काम करता था और जब अभी डबल इंजन की सरकार है, तो वह घट कर 2 परसेंट से भी नीचे चली गई है। प्रधान मंत्री जी एक बार मोतिहारी गए और चुनाव के समय में, अभी जैसे बजट आया है, बिहार बिहार हो रहा है, बिहार में बहार फिर से आ रही है, इसी तरह से वहां पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगली बार जब मैं आऊँगा, तब इस बंद चीनी मिल की चिमनी से धुआँ निकलता रहेगा और इसी चीनी मिल की चीनी से मैं आप लोगों के साथ बैठ कर चाय पियूँगा। आज भी चीनी मिल उसी स्थिति में है, कोई चीनी मिल खुली नहीं, किसी बंद चीनी मिल की चिमनी से धुआँ नहीं निकल रहा है। यह स्थिति है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार को एक systematically neglect करने की आपकी राजनीतिक £ है, केवल वहाँ के लोगों का वोट लेना है और फिर बिहार को पिछड़ेपन का शिकार बना कर रखना है। मैं इसके पीछे भी एक बड़ा कारण देखता हूँ। बिहार को इसलिए systematically neglect किया जा रहा है, क्योंकि इस देश में जो बड़े उद्योग घराने हैं, बड़े उद्योग-धंधे वाले लोग हैं, उनके दबाव में आपकी सरकार काम करती है, आपकी सरकार नीतियां बनाती है और वे लोग चाहते हैं कि बिहार एक लेबर फैक्ट्री के रूप में पूरे देश में काम करे। बिहार के लोग बिहार से निकल कर उन बड़े कल-कारखानों में काम करें, ताकि उनका उद्योग-धंधा ठीक से चलता रहे।

इस बार एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी घोषणा हुई। यह चुनाव का साल है, वहां 6-8 महीने बाद चुनाव है। वहां एक पताही एयरपोर्ट है। इसी तरह, वहां पूर्णिया और भागलपुर का एयरपोर्ट है, जो पहले काम करता था, लेकिन फंक्शनल नहीं हो पाया। मेरे एक और साथी हैं, जो लोक सभा में हैं, वे भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि सोनपुर में एक एयरपोर्ट शुरू हो जाए, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी जब से आपके साथ सरकार चला रहे हैं, तब से वे इमोशनली एक बात लगातार कहते आ रहे हैं कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, बिहार में लगातार बाढ़ और सूखे की समस्या रहती है, जब तक आप बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे, तब तक बिहार लो इनकम स्टेट से मिडल इनकम स्टेट के

£ Expunged as ordered by the Chair.

ग्रुप में नहीं आएगा और बिहार की आर्थिक बदहाली दूर नहीं होगी, लेकिन कभी भी आपकी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए हम इस बात को फिर दोहराते हैं।

पटना विश्वविद्यालय की मांग भी मुख्य मंत्री जी हमेशा पब्लिक मीटिंग्स में करते रहे, लेकिन उनकी भी एक नहीं सुनी गई। पटना विश्वविद्यालय जैसा लब्धप्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जिससे हजारों अफसर पढ़कर निकले, हजारों बड़े-बड़े डॉक्टर्स निकले और हजारों इंजीनियर्स निकले, जिनका देश में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसको भी सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। बिहार के साथ इस प्रकार की उपेक्षा और अपमान लगातार हो रहा है। ...(**समय की घंटी**)... क्या हमने आपको इतना विद्वान इसीलिए कहा था? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : अब आप खत्म कीजिए।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : बिहार जैसे गरीब स्टेट पर इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। बिहार मेहनत और ज्ञान का प्रतीक है और वह बुद्धिज्म, जैनिज्म तथा सिखिज्म का कल्चरल सेंटर रहा है। अगर आप बिहार की उपेक्षा और अपमान ज्यादा दिनों तक करेंगे, तो वहां के लोग कम इनकम वाले हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन पोलिटिकली वह एक सजग स्टेट है और आने वाले चुनाव में वे आपको सीख देंगे, आपको कान पकड़कर बाहर करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहकर आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हालांकि, आपने बीच में घंटी बजा दी, लेकिन कोई बात नहीं, बिहार के साथ इस तरह का अत्याचार आप न तो कीजिए और न सरकार को करने दीजिए, तभी जाकर इस बजट का कोई मतलब होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : धन्यवाद।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : सर, जिस दिन बजट आया था, उस दिन हम अपने एक सीनियर कलीग से बात कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि यह किस तरह का बजट है, तो मेरे सीनियर कलीग ने कहा कि यह बजट वोकल और लोकल लोगों के बीच में फंस गया है। जो 2% लोग हैं, जिनको 12 लाख का झुनझुना यह कहकर थमाया जा रहा है कि उतनी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन 98% लोग, जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उन लोकल लोगों का भी आप ख्याल कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : धन्यवाद। सुश्री सुष्मिता देव जी।...

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : सर, यह आदरणीय जयराम रमेश जी ने ही कहा था। ...(**व्यवधान**)... जब इन्होंने कह दिया, तो मैं बता रहा हूँ कि लोकल और वोकल के बीच में यह बजट फंस गया है। ...(**व्यवधान**)... आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : धन्यवाद। सुश्री सुष्मिता देव जी।

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to start by thanking my Party for giving me the opportunity to speak on the Budget for 2025-26. I am honoured for two reasons as I am positioned very uniquely in this House. The first reason is that I come from a State in the North-East, my vote is in Assam, but 50 MLAs across Bengal have voted me into the Council of States. I thank my leader, Ms. Mamata Banerjee.

The second and the more significant reason why I am positioned uniquely in this House is because when I look to my left and see so many Members of Parliament who come from the North-Eastern States, they tend to remain silent on all the ailing issues that the eight States of the North-East face. I feel lucky that when I look on this side of the House, when I look at the Opposition, I think, apart from Mr. Bhuyan, I am the only other Member of the Parliament in the Opposition. The silence on that side is killing - not a word on what happened in Manipur, not a word on what is happening in Assam and the NRC, not a word on the Nagaland Accord, not a single word of sympathy, not a single word of apathy.

Sir, I would like to say that this Budget is an insensitive Budget; insensitive to the people of the country and more insensitive, in particular, to the North-East of India. I heard Prime Minister Modi say after the Budget that the sop that has been given to the middle class is going to have a multiplier effect. But, when it comes to the North-East, all the things that ail this nation, whether it is price rise, whether it is unemployment, whether it is lack of investment, the only multiplying effect that I know is that all these problems multiply as we go towards the North-Eastern States. I would like to say that it has consistently been the vision of the Government of India that they have given the States of North-East special status and special focus. Today, I recall, with a lot of respect and great tribute, our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. It was his vision when he, in 1991, said that if we want the North-Eastern States to develop, then we have to Look East. What he meant was that the North-East was the gateway to the South-East and East Asia. It was a landlocked region of India and if it had to trade, if it had to create employment, if it had to attract investment, then we have to Look East. Whatever efforts were made by Dr. Manmohan Singh's Government over decades have been undone by Prime Minister Modi by one single incident in one State, which is the State of Manipur. The Prime Minister Modi changed the Look East Policy to Act East Policy, but today, till the gateway to the South-East Asia, which is the State of Manipur, continues to burn, the Act East Policy is destined to fail. It is destined to fail, and I would like to say that today, with our security concerns with China, the political situation in Myanmar and the political situation in Bangladesh, I can tell you with great surety that the prospects

of the economy of the North-Eastern States growing are rather dismal. I heard the hon. Finance Minister talk about Bihar. I heard the hon. Finance Minister talk about middle-class with the Delhi elections which were due. But, I never once heard the name of Manipur from the Finance Minister where 60,000 people have been displaced, where hundreds of people have been murdered and butchered and women raped and children who are out of schools. *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : जब आपका नम्बर आएगा, तब आप बोलिएगा।

MS. SUSHMITA DEV: Thousands have fled from Manipur to different parts of India, whether it is Kolkata, whether it is Assam, whether it is Delhi. *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : जब आपका नम्बर आएगा, तब बोलिएगा। आप ऐसा मत कीजिए।

MS. SUSHMITA DEV: Today, what the Finance Minister should have said is not just Bihar, but she should have promised a comprehensive package for the rehabilitation of Manipur, which she did not. There should have been a comprehensive package because what happens to Manipur impacts all the North-Eastern States. Today, we cannot accept just a resignation of the Chief Minister as a solution to Manipur, and if the Manipur tapes are investigated, we will see, we will find out, and we want to know if it was State-sponsored mahyem that was created in Manipur. *...(Interruptions)...*

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir*...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : आप समझ नहीं रहे हैं, फिर वह उनके टाइम में जुड़ जाएगा। जब आपका नम्बर आएगा, तब आप जवाब दीजिएगा।

MS. SUSHMITA DEV: Now, I come to the cuts in the Budget. The nine lakh rupee Central pool of resources have been slashed by 30 per cent. *...(Interruptions)...* The North-East Special Infrastructure Development Scheme's allocation has been slashed by 39 per cent. *...(Interruptions)...*Special development package has been slashed by 28.8 per cent. *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : आप समझ नहीं रहे हैं, फिर वह उनके टाइम में जुड़ जाएगा। जब आपका नम्बर आएगा, तब आप जवाब दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)...

MS. SUSHMITA DEV: Grants under PM-DevINE, that is, the Prime Minister's Development Initiative for North East Region, have been slashed by 36 per cent. Grants to Autonomous Councils has been slashed by 96.6 per cent. Grants by Ministry of Home Affairs have been decreased by 45.6 per cent, and I can go on and on and on. When is this lip service to the North Eastern States going to stop, I want to know from the hon. Finance Minister? Madam, please tell us about '*achche din*'. Nobody knows about '*achche din*'. What happened to that? Then, we were all hoping for a 'New India'. Nobody knows what happened to 'New India'. Now, she says that our new destination is 'Viksit Bharat by 2047'. I do not think, I will be alive and here in this Parliament to see what happens in 2047. Sir, I want to raise an important issue about my own State, the State of Assam. I thank the Government for giving us a urea plant. I have no problem with it, but this Government has systematically destroyed the public sector enterprises in the State of Assam. Two paper mills owned by the Hindustan Corporation have been shut down. We heard about 'Advantage Assam' from hon. Member of Parliament who just spoke before me, and, I want to say that more than 50 per cent of the investment that 'Advantage Assam' has attracted is from public sector undertakings and not private investment.

Today, we hear that all the capitals of the North Eastern States will be smart cities.Let me give you just one example. Kalitaji is here. One flash flood in Guwahati, an eight year old boy falls from the scooter and gets drowned in the current of water! A flash flood caused it in Guwahati! Sir, the hon. Finance Minister talks about 'Heal in India' initiative and Medical Tourism. Medical tourism, for us in the North East, is that for small surgeries, for minimal treatments, we have to go to Chennai, Kolkata and Delhi. That is medical tourism for us in the North East.

Let us talk about UDAN scheme. I come from a remote area in Assam called Silchar. I have been repeatedly saying it in this Parliament and I am pained to say that there is not a single route, I repeat, not a single route, from the Silchar airport which is recognized by UDAN. I ask myself why.

'सबका साथ, सबका विकास' बहुत बड़ा स्लोगन है। I want to say that it is a big slogan but this Government has to realize that without strong States, you cannot have a strong Centre. When is this Government going to realize this? Sir, the hon. Finance Minister said that she will start an index to see which are the States that are friendly to private investors. वित्त मंत्री जी, एक और इंडिकेटर उसमें लगा दीजिए। Please have an indicator of the States which you deprive, the States you deny, and the States which thrive despite that. I am talking about the State of West Bengal. Please add that indicator and you will see that West Bengal is ready, you will see that Mamata Banerjee has succeeded in Bengal not because of Modi Government but despite the Modi Government. ...*(Interruptions)*... मैं यह कहना चाहती हूं कि असम के

लिए भी एक इंडेक्स बनाइए ...(**व्यवधान**)... असम में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए एक नया इंडिकेटर बनाइए ।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : आप डिस्टर्ब मत कीजिए। जब आपका नम्बर आएगा, तब आप जवाब दीजिएगा।

सुश्री सुष्मिता देव : उस इंडिकेटर में हमें यह दिखना चाहिए कि असम में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला) : यदि आप बीच में बोलेंगे, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)... जितना आप डिस्टर्ब करेंगे, उतना उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा।

MS. SUSHMITA DEV: £ शायद इसमें असम सबसे आगे होगा।

Mr. Vice-Chairman, Sir, I hope, as Parliamentarians, we go beyond the headlines and look at the fine print to see that, in effect, it is an insensitive Budget which does not talk about unemployment, which does not talk about price-rise and which does not address the ailing and burning issues of this country.

6.00 P.M.

It is an absolute and total neglect of the North Eastern States and Bengal. Unless you rectify your ways, you will be routed from North-East and you will be routed from Bengal because, Sir, let me submit that today people are suffering and people's voice in a democracy is the loudest voice. I can tell you that today Assam has got a urea plant and the one single reason is Assam is headed for elections, and Mr. Biren Singh has been asked to resign only because the entire tribal community of India has moved away from the Bharatiya Janata Party. With those words, I once again thank the party for giving me this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Thank you. Now, Shri P. Wilson.

SHRI P. WILSON: Thank you, Vice-Chairman, Sir. I wanted five more minutes. You should not be like a Finance Minister. Be gracious enough to give me five more minutes.

£ Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): When you give your next speech, take another five minutes in that speech, not in this one.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, this Budget is not a Budget for the people of this country. It is a Budget of missed opportunities, misaligned priorities and economic stagnation. In a nutshell, this is not a Union Budget; this is a coalition Budget, aimed at political appeasement rather than national development. This does not reflect inclusive growth.

Sir, I will list out how Tamil Nadu has been ignored in this Budget. Tamil Nadu is the second largest contributor to the GDP, third in the GST and fourth in the direct tax. However, this year, it is ranked 15th in Railway Budget allocation. This year, the allocation is Rs. 6,626 crores, which is just 2.5 per cent of the national Railway Budget. A State like Madhya Pradesh has been allocated Rs. 14,745 crores and Uttar Pradesh has been allocated Rs. 19,858 crores. For every one rupee which Tamil Nadu gives to the Union kitty, it got only 26 paise last year. Now, this has still gone down. Our request to approve metro rail projects in Tamil Nadu, especially in Madurai and Coimbatore, is neglected.

(THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair*.)

No new high-speed rail line is approved and no new expressway is announced. Nothing is there on FAME bus scheme in this Budget. There is no allocation for Chennai metro rail project. Other States like UP has metro available in five cities, Maharashtra has metro in four cities, but we are not getting enough funds even for one metro project which is in Chennai. Coimbatore's AIIMS project is totally ignored. The Madurai AIIMS, inaugurated with fanfare by the hon. Home Minister in 2019, is still moving at a snail's pace. It looks like that the first batch of students will graduate from a temporary building without even seeing the Madurai AIIMS. In December 2023, when cyclone Michaung and flood hit Chennai and other coastal districts, our Government demanded Rs. 37,000 crores for damages and compensation. But, unfortunately, Union Government gave only a paltry sum of Rs. 276 crores. However, when a cyclone hit Gujarat, the Union Government immediately released Rs. 5,000 crores when the hon. Prime Minister visited. Sir, no new major National Highway expansion or railway corridor projects were sanctioned in Tamil Nadu. Higher allocations were made for Gujarat and U.P. under the Bharatmala and railway modernization. There is reduction in Rural Development Fund which impacts Tamil Nadu. This reduction will affect crucial rural infrastructure and poverty alleviation

programmes in Tamil Nadu. There is insufficient allocation for smart cities and urban development. Cities like Chennai, Coimbatore and Madurai received no specific urban development allocation despite their crucial role in the Smart Cities Mission. The Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor project was not given additional funding despite repeated requests from the State Government. This will now slow down the industrial and manufacturing sector growth in Tamil Nadu.

Sir, there is a disproportionate tax devolution and GST compensation to Tamil Nadu tax share. There is a 10.5 per cent increase in devolution to other States, but no specific relief or GST compensation is given for Tamil Nadu. The State has been demanding higher GST compensation due to the revenue loss post-GST implementation. There is no special package for fishermen affected by Sri Lankan territorial issues and even for the climatic change. A Blue Economy Fund to support the fishing industry is absent in the Budget which was expected. There is no increase in the funds for disaster management for Tamil Nadu. Tamil Nadu is prone to floods and cyclones. It expected higher allocation for disaster resilience. The disaster management grant was increased by only five per cent which may not be sufficient during disaster time to meet any crisis. There is a neglect of Tamil Nadu renewable energy push. The Budget focussed more on nuclear energy. Tamil Nadu, a leader in wind and solar energy, was not allocated additional funds for its renewable projects. We expect higher Central grants for Tamil Nadu offshore wind energy projects. There is no special status or financial support for Tamil Nadu, which has demanded a special financial package considering its high revenue contribution to the Centre.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है।

SHRI P. WILSON: Sir, another five minutes.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया समाप्त कीजिए। Not at all.

SHRI P. WILSON: I will complete, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : हाँ, कंप्लीट कर लीजिए।

SHRI P. WILSON: There is less per capita funding compared to many northern States. In the Union Budget 2025, several sectors experienced a decrease in allocation compared to the previous fiscal year. (*Time-bell rings.*) Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : श्री एस. निरंजन रेड्डी।

SHRI S NIRANJAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, for me, the Budget presents a mixed bag. It has a continuity and commitment. It ticks off the macro boxes well. It has a proper fiscal glide path. It is showing the way towards fiscal consolidation. The capital expenditure could have been little more, but it has been maintained constant because last year the utilisation was not complete. Overall, it seems like a sound Budget on macro factors, but the Budget also has its challenges. If I can take a neutral point of view, the country faces global headwinds in terms of economic prospects. There is a slowdown of global growth. There is a slowdown of global trade. So the Government and the Finance Minister have to confront these challenges. I look at the Government trying to stick to fiscal discipline. This is my starting point. I would like to compliment the Finance Minister and the Government. Maybe it shows some light in relation to the recent NITI Aayog Report about some of the States needing to learn something from the Centre trying to stick to this fiscal discipline. I may have a few differences with the hon. Finance Minister with regard to the allocation, but I would like to start by complimenting the Government that they have remained fiscally responsible. The biggest flash the Budget makes is in terms of the tax relief that is granted to the middle class. All of us welcome it because these are the classes that have been contributing to the direct taxes which constitute the largest chunk of the revenue that the Government gets. But one lakh crore rupees is substantive money. I would want to buy into the Government's and the hon. Finance Minister's belief that this will spur the consumption growth leading to the money funnelling back into the economy, but I think the Government would have to be mindful. One lakh crore rupees per year is substantive amount. The total education budget estimate for the next year is one lakh twenty-eight thousand crore rupees. For health, it is ninety-nine thousand eight hundred and fifty-eight crore rupees. For the Ministry of Electronics and Information Technology, the total Budget Estimate is twenty-six thousand and twenty-six crore rupees. I notionally look at this one lakh crore rupees being divided amongst the Education, Health and Ministry of Electronics and Information Technology, if there was no tax cut. I am just giving a hypothetical example. I am not suggesting there should not be a tax cut.

It would have meant Rs. 33,000 crore more for education. One-third of that amount would have meant that the education sector would have got 25 per cent jump on the Budget Estimates that the Education Department has. Then, Rs. 33,000 crore for health for one year would have been a 33 per cent growth on the amounts that would be allotted. For Ministry of Electronics and Information Technology, which I

believe is going to be the engine of driving India's growth tomorrow, the growth would have been 130 per cent. Let us just pause for a minute and think that if this Rs. 1 lakh crore could hypothetically be divided amongst these three, the growth and the impetus that each of these sectors had got would have been stupendous. But, as I mentioned, I would want to be optimistic. Let me buy into the Government's vision; let me buy into the hon. Finance Minister's vision that this will spur consumption growth. I am slightly sceptical, but even if it were to translate into a 50 per cent reality, it would still be worth it because a large section contributing to the Indian economy is felt rewarded by the Government. Those sections will feel that the Government is listening to them, but it is time that most of that money —I would appeal to those people who are getting those tax monies — is ploughed back into the Indian economy. Do not splurge it on travelling abroad; please travel in India. Do not splurge it on spending on foreign goods; please spend it on goods that are manufactured in India. The Government made an overture to you. If you respond and if you were to give Government a helping hand, you will get more reliefs later. If this does not work for the Government, then, the tax-paying class needs to understand that they are not repaying the Government's faith and the Government may not want to extend these kinds of benefits. Please note this as a warning for ourselves. I have touched upon three areas that could have immensely benefited, if the amounts were to be contributed to them, I will touch upon only these three areas as my theme on the three suggestions that I want to make.

Sir, within the limited allocation that is made, one area I want the Government to really speed up this process, but which is sadly lacking, is the internet connectivity to schools. The UDISE report of 2023-24, which is of the Government of India, shows that only 57 per cent of the Indian schools have functional computers and only 53 per cent of the schools have internet access. If we have to take up digital education, and that is the easiest way to scale and give education to large masses, I would hope that the Government can get these figures to reach 100 per cent as soon as possible.

Sir, on health, I want to suggest to the Government two issues. One is that we need to have Artificial Intelligence rollout in terms of providing healthcare benefits to the people, because that will really scale up this whole process. I also find, one looming threat that we face is antimicrobial resistance. The Government has been considerate; it has increased the Budget allocation from Rs. 52 crore to Rs. 54 crore. But I want the Ministry to note that the utilisation has come down from Rs. 38 crore in 2022-23 to Rs. 17 crore in 2023-24. So, the loss, in notional GDP terms, is going to be very high for India. This is a looming crisis. Everybody is forgetting about it because this does not immediately shriek for attention, but it is one of the largest

crises that will confront India in the next two to three years. I want the Ministries to give it full attention.

Sir, then, the last topic that I want to touch upon is the Ministry of Electronics and Information Technology. As I said in the earlier part of my speech, this Ministry is going to be the greatest engine driver of growth because this Ministry will work across sectors. It will work through education; it will work through health; it will work through every sector that is possible. The allocations are very minimal. Then comes the Centres of Excellence. India cannot have one Centre of Excellence for one discipline in one part of the country. I think it is time that by now we should have Centres of Excellence in every zone, if not in every State. I would request the Government to, at least, make provisioning from next year onwards that these Centres of Excellence are given to each State.

Sir, since I have another 30 seconds, the last topic is urban development. I would compliment the Government for having this Urban Challenge Fund and an amount of Rs. 10,000 crore is allotted. The only recommendation and suggestion I have for the Government is, if possible, please use 80 per cent or 90 per cent of this fund for urban planning.

States are not doing urban planning. All our cities are becoming cesspools. Sir, 40 per cent of Indian population is going to be living in cities by 2035 or 2040. And, no urban planning goes into the growth of cities. We do not have new greenfield cities. Please plan five or ten new greenfield cities. Make provision out of this urban fund.

And, with that, Sir, I would want to wish the Government the best. As I said, I do not think it is a great Budget, but it is a good Budget. I am willing to live with it. But, I will feel it is great if they, actually, implement the schemes well. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद, रेड्डी साहब। माननीय प्रो. राम गोपाल यादव।

प्रो. राम गोपाल यादव : श्रीमन्, मैं केवल चार-पाँच मिनट बोलूँगा, आपको घंटी बजाने का अवसर नहीं दूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : हम आपके लिए घंटी क्यों बजाएँगे?

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : सर, इस बजट में देश की तरक्की के लिए, विकसित भारत के लिए जो सबसे महत्त्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पिछले साल का जो बजट था, उसकी तुलना में in terms of percentage of GDP, इन चारों सेक्टर्स में इस बार बजट कम हुआ है। एग्रीकल्चर में पिछले वर्ष यह 2.7 परसेंट था, अब 2.5 परसेंट रह गया है। टोटल में 5-10 करोड़ बढ़ जाए, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन

comparison तो हम पिछले साल के जीडीपी के हिसाब से ही करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत जरूरी है, उसमें पिछली बार यह 3.4 परसेंट था, अब यह 3.1 परसेंट है। हेल्थ में तो यह 2 परसेंट भी नहीं है, 1.97 परसेंट है, जबकि लक्ष्य रखा गया था कि कम से कम 2.5 परसेंट हो जाए। अगर यह 2.5 परसेंट भी हो जाए, तो जो out of pocket expenditure है, वह बहुत कम हो सकता है। अभी आँकड़े कुछ कहते हों, लेकिन वास्तविकता यह है कि 60 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनको अपनी जेब से इलाज का पैसा देना पड़ता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है। एक रिपोर्ट आई थी, जब मैंने दो-तीन साल पहले हेल्थ कमिटी में कुछ एक्सपट्र्स को बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि हर साल 4-5 परसेंट लोग केवल बीमारी के इलाज पर पैसा खर्च करने की वजह से below poverty line में चले जाते हैं। एजुकेशन में 2020 में ही नई एजुकेशन पॉलिसी में 6 परसेंट का लक्ष्य था, वह अभी four point something है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, अगर उनको बजट में नजरअंदाज किया जाएगा, तो विकसित भारत नहीं बन सकता है, आप बात कितनी भी करें।

सर, मुझे एक बात की बहुत चिंता है कि रेपो रेट कम किया गया है। आप इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। इसका दुष्परिणाम क्या होगा! यहाँ बैठे हुए लोग, माँझी जी calculate करिए, अगर हम बैंक से 50 लाख रुपए का कर्ज लें, तो पिछली बार की तुलना में जो रेपो रेट कम हुआ है, उसमें हमें केवल 1,950 रुपए का लाभ होगा। 1,950 रुपए का लाभ 50 लाख रुपए का कर्ज लेने पर! लेकिन बैंकों का क्या हाल होगा! बैंकों से तो लोग हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए लेते हैं। बैंकों का स्वास्थ्य बहुत खराब होगा। दूसरे, अब fixed deposit में कोई जमा नहीं करना चाहेगा। बैंकों में पैसा नहीं जाएगा, बैंक्स कमजोर होते जाएँगे। लोगों को, अर्थशास्त्रियों को यह आशंका है कि अगर यही स्थिति रही, तो बैंक्स डूबने लग सकते हैं। जिन लोगों ने अपना एक-एक पैसा जमा किया है, आम लोगों ने, बड़े लोगों का कर्ज तो write-off भी हो जाता है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा जमा किया है, उनका पैसा डूब जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह प्रावधान है कि आपका चाहे जितना पैसा जमा हो, अगर बैंक डूब जाए, तो एक लाख रुपए देंगे। चाहे आपका 100 करोड़ जमा हो, चाहे 200 करोड़ जमा हो, चाहे 50 लाख जमा हो, वे केवल एक लाख देंगे। यह स्थिति बहुत ठीक नहीं है।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी का ध्यान एक और चीज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो NCLT है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जो लगातार हो रहा है। यह बैंकों को नुकसान पहुंचा रहा है और कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा रहा है। जैसे NPA होता है, यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर 50,000 करोड़ का कर्ज है, उसने 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और उसे केवल 40,000 करोड़ में नीलाम किया गया, तो 10,000 करोड़ तो haircut में चला गया, बैंक का loss हुआ, लेकिन अब बैंक का इससे कोई लेना-देना नहीं है। किसी की जो 2 लाख करोड़ की जमीन थी या कोई प्रॉपर्टी थी, वह किसी व्यक्ति विशेष को केवल 40,000 करोड़ में मिल गई। यह वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय की नाक के नीचे हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वे इस मामले की जांच करें कि किन-किन लोगों ने NCLT के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसकी actual value क्या रही होगी और haircut के द्वारा बैंकों को कितना नुकसान पहुंचाया गया है। इस corruption पर रोक लगाने की जरूरत है। वित्त मंत्री जी अगर कभी टाइम देंगी, तो मैं उन्हें personally कुछ ऐसे examples दूंगा कि उन्हें आश्चर्य होगा कि यह क्या हो रहा है।

महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं अपनी बात यही कह कर खत्म करना चाहता हूं कि अगर देश को विकसित करना है, तो जो महत्वपूर्ण sectors हैं, उनका allocation बढ़ाया जाए तथा NCLT के जरिए यह जो भ्रष्टाचार लगातार किया जा रहा है और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, इसको रोका जाए। थैंक यू, सर।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद, प्रोफेसर साहब। श्रीमती सुलता देव; three minutes.

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा) : जय श्री जगन्नाथ। Thank you, Vice-Chairman, Sir, for the opportunity. फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, मैं भी कुछ आंकड़े देना चाहती हूं। Global Peace Index, India is at 116th rank, Global Happiness Index, 126th; Gender Gap Index, 129th; Global Hunger Index, 105th; Human Development Index, 134th; Passport Index, 84th; Gender Inequality Index, 129th; Corruption Perceptions Index, 93rd; Press Freedom Index, 159th; Sustainable Development Goals Index, 112th — यह है विकसित भारत की छवि। कौन सा 'अमृत काल'? हमको जो गुलाबी चित्र दिखाया जा रहा है, वह सुनने में अच्छा है, मगर कौन सा 'अमृत काल' आ गया? ऐसा 'अमृत काल' आ गया, जब गरीब महंगाई के नाम का जहर खाकर अपना पेट भर रहा है, मगर फिर भी अमृत काल, अमृत काल बोलते जुबान नहीं थकती। यह 'अमृत काल' आप लोगों को और बिस्कुट मीडिया को मुबारक हो।

मान्यवर, अब मैं जीडीपी के ऊपर आती हूँ। इन्होंने कहा था कि हम GDP को ऊपर लाएंगे। GDP ऊपर आ रही है, लेकिन कौन सी GDP? Gross Domestic Product नहीं, तो यह कौन सी GDP ऊपर आ रही है? गैस, डीजल और पेट्रोल की GDP ऊपर आ रही है, आज यह 100-100 रुपये में आ रहा है। यही GDP की बात कर रहे थे! ये 'सबका साथ, सबका विकास' कह रहे थे, तो कहां गया 'सबका साथ, सबका विकास?' यहां पर पूँजीपतियों का साथ और गरीबों का विनाश ही विनाश हो रहा है। यह है - आज का 'सबका साथ, सबका विकास!'

मान्यवर, जब प्रधान मंत्री जी Motion of Thanks on President's Address के अवसर पर ओडिशा के बारे में बोल रहे थे, तो उन्होंने पारादीप-हरिदासपुर रेलवे लाइन के बारे में कहा कि यह उनके कालखंड में कंप्लीट हो गया। मगर उसी कालखंड में खुर्दा-बोलांगीर लाइन के पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? पारादीप-हरिदासपुर रेलवे लाइन तो मिनरल्स लेने के लिए कंप्लीट हो गया, मगर खुर्दा-बोलांगीर लाइन में मिनरल्स नहीं हैं, यह तो वहाँ के पैसेंजर्स के लिए है, इसीलिए वह कंप्लीट नहीं हो रहा है। यह कैसा बजट हुआ कि बस 'बिहार-बिहार' सुनाई दे रहा था। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यह बजट एक political instrument बन चुका है। इस बजट में ओडिशा के लिए उतना कुछ है ही नहीं, क्योंकि जहां इलेक्शन होना होता है, बजट वहीं दिया जाता है। बार-बार यही हो रहा है। यह federal structure को मारने की £ है। ओडिशा 'Special Focus State' status की demand कर रहा है, 'Special Category' status की

£ Expunged as ordered by the Chair.

demand कर रहा है, special disaster fund की demand कर रहा है, मगर यह उसे नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदय, अगर आगे देखें, तो 5-trillion economy के बारे में जो बात की जा रही है, उसमें हम कहां हैं, यह कैसे होगा, यह भी एक गुलाबी चित्र है। 5-trillion economy कैसे हो सकती है? जब एक डॉलर की रुपए में कीमत सेंचुरी मारने की कगार पर खड़ी है, तो आप कैसे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? यह कैसे होगा? यहाँ पर जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, सोशल वेलफेयर के बजट को घटाया गया है। टेलिकॉम, रेलवे, बैंकिंग में ओडिशा का शेयर नेशनल एवरेज से बहुत कम है। अगर ओडिशा डिमांड भी कर रहा है, 20 सांसद भी दिया है, फिर भी अनदेखा किया जा रहा है। यदि देखा जाए, तो पता चलेगा कि ओडिशा को नेशनल एवरेज से तो कम मिला ही है और पड़ोसी स्टेट्स से भी कम मिला है। रेलवे बजट decline कर रहा है। पिछली बार इसके लिए 2.62 लाख करोड़ रुपए था, जबकि इस बार 2.55 लाख करोड़ रुपए है। आईटी और टेलिकॉम बजट पिछले साल 1.16 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार 95.289 हजार करोड़ रुपए है। ऐसे कैसे चलेगा? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यह कहाँ का विकास हो रहा है? ओडिशा में हम लोग बोलते हैं कि इंटरनेट नहीं है, बैंक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, सब जगह रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया आप समाप्त करें।

श्रीमती सुलता देव : आप कहाँ जा रहे हैं? ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं आधा मिनट में conclude कर रही हूँ। सर, हमारे ओडिशा में अभी एक गाना बहुत ट्रेंड में है, बहुत वायरल है।
& "You recognised the value of gold, but failed to value the worth of a human being."

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्या, आपका समय समाप्त हुआ।

श्रीमती सुलता देव : सर, आज ये गरीब मनुष्य को चिह्न नहीं पा रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, I stand here to support this Budget on behalf of my party, Tamil Maanila Congress (Moopanar). This Budget, no doubt, drives to push Viksit Bharat, 2047. The proposed measures include important sectors — poor, youth, farmers, and women. Sir, no doubt, the middleclass provides strength for India's growth and I would appreciate the hon. Finance Minister for giving this very important Budget. I would also say this is the most pro-middleclass Budget in India's history. By raising the Nil Tax Slab of income tax payable from Rs. 2.5 lakh in 2014 to Rs.5 lakh in 2019 and Rs.7 lakh in 2023 is now being raised to Rs.12 lakhs in 2025-26. As a result of this, about Rs.1 lakh crore, in direct taxes, could be foregone. I am

& English translation of the original speech delivered in Odia.

very happy, Sir, that India's middleclass could use this extra savings for driving their aspirations and quality of life which is the need of the hour in the country today, which the hon. Finance Minister has reflected in her Budget.

Hon. Prime Minister has always a special focus on Tamil Nadu, be it direct or indirect. As recommended by 15^{th} Finance Commission, Tamil Nadu's share of Central taxes is 4.079 per cent. The amount to be received by the State has been increased from Rs. 52,491.88 crores in the revised Union Budget estimates. It was only Rs. 50,873.76 crores in the initial Estimates. Sir, thanks to the hon. Finance Minister, an outlay of Rs.1.5 lakh crores is proposed for 50-year interest-free loans to States for capital expenditure and investments for reforms, besides incentives to boost local manufacturing in areas like mobile phone, electric vehicles, textiles, etc. Tamil Nadu accounts for 40 per cent of India's textile production with Tirupur, Coimbatore, Erode and Karur as major centers. The new outlay would further boost Tamil Nadu industries. A six year mission has been proposed for Atmanirbhar Bharat in pulses. It will, definitely, focus on improving productivity, domestic pulse production, assuring price for farmers and climate-resilient seeds.

Sir, this effort will enhance cotton and pulses production. It will benefit the farmers of Tamil Nadu, especially in Madurai, Virudhunagar and Coimbatore region. Sir, Kisan Credit Card facility, short-term loans will help 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. I am sure, lakhs and lakhs of farmers will be benefited in Tamil Nadu with these schemes. At the same time, Cauvery river water is the need of our farmers. I would request the Central Government that the Cauvery Board should be given importance and the award should be given in favour of the State of Tamil Nadu, so that lakhs and lakhs of our delta region farmers will be helped, especially, in Thanjavur. Sir, KCC loan has been increased from Rs. 3 lakhs to Rs. 5 lakhs under the Modified Interest Submission Scheme; it will help us. The Swadesh Darshan 2.0 and the PM Vishwakarma Yojana could massively boost tourism in Madurai, Mahabalipuram and Kanyakumari.

Sir, Rs. 6,626 crores have been allocated for Tamil Nadu railway projects. It is increased by 4 per cent from last year. The average outlay between the year 2009 and 2014 for the State was only Rs. 879 crores. The current allocation to Tamil Nadu is eight times higher. It could support doubling, new lines and station development. I thank the hon. Minister for this concern.

To conclude Sir, I would like to say that this Budget has given a powerful message to the country for its future progress. The people of the nation trust the Government under the hon. Prime Minister. The recent Delhi Assembly election

results is the outstanding example for the success of the Union Budget. Thank you, Sir.

श्री शंभू शरण पटेल (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मैं पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार को उसके तीसरे कार्यकाल के प्रथम आम बजट के लिए धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने बिहार की 14 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु इस आम बजट में बहुत से प्रावधान किए हैं, एक्स्ट्रा पैकेज दिया है। इसके लिए मैं आपको और वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, कुछ महीने पहले बिहार के अति पिछड़ों के मसीहा, अति पिछड़ों और पिछड़ों के लाल, गुदड़ी के लाल, बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को प्रधान मंत्री जी ने "भारत रत्न" देने का काम किया है। इसके लिए मैं पूरे अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, मैं वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वित्त राज्य मंत्री और उनके अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने, मध्यम वर्ग को पूर्ण राहत देने, समाज के सभी वर्गों की रक्षा करने, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने तथा सशक्त, समावेशी, सर्वस्पर्शी और राष्ट्र प्रथम की भावनाओं से ओत-प्रोत बजट इस सदन में पेश किया है। महोदय, अभी कुछ देर पहले हमारे बड़े भाई, कांग्रेस के सांसद, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी को मैं सुन रहा था, जो पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। वे अभी सदन में नहीं हैं। वे कह रहे थे कि बिहार में...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, वे सदन में नहीं हैं, लेकिन सदन का नियम यह है कि जो वक्ता बोले, उसको कम से कम तब तक सदन में रहना चाहिए, जब तक उसके बाद कोई दूसरा वक्ता बोले। यह संसदीय परंपराओं में है। अब आप अपनी बात कहिए।

श्री शंभू शरण पटेल : ठीक है, उपसभाध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं बिहार जैसे आकांक्षी राज्य से आता हूं। वर्ष 2005 के पहले बिहार में लगभग 50 वर्षों तक यूपीए की सरकार ने शासन किया, जिसमें कांग्रेस ने सबसे अधिक शासन किया। वर्ष 1990 से वर्ष 2005 के दशक में आरजेडी का शासनकाल रहा। महोदय, कांग्रेस और कम्युनिस्ट साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाती थीं। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन उस कालखंड के बारे में जब हमारे बुज़ुर्ग लोग बताते हैं, तो सुनकर रूह कांप जाती है। उस समय हाई कोर्ट को भी यह बोलना पड़ा था कि बिहार में शासन नहीं, बल्कि जंगलराज है। उस जंगलराज के पुरोधा कांग्रेस और आरजेडी वाले हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी वालों को नसीहत देने का काम करते हैं। वर्ष 2005 के पहले बिहार के पूरे 38 जिले उग्रवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, जातीय नरसंहार और संगठित अपराध के लिए जाने जाते थे। वर्ष 2005 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई है, तब से लेकर अब तक बिहार में सुशासन है। कोई भी अपराध करके वहां नहीं बच सकता। वहां अपराधी मारे गए या जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए या अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आ गए।

महोदय, अखिलेश जी ने कहा है कि बिहार को इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है, तो मैं उनको सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि या तो उनको अपने एलओपी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि माननीय मल्लिकार्जुन खरगे जी ने बजट भाषण में कहा था कि लगता है यह बजट सिर्फ बिहार के लिए है। माननीय अखिलेश जी पहले आपस में फैसला कर लें कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे जी के साथ हैं या नहीं हैं। वे उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं।

महोदय, वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी। उसके पहले बिहार में सिर्फ एक एयरपोर्ट 'जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा' था। वर्ष 2014 के बाद बिहार में दरभंगा जैसे जिले में - जो उत्तर बिहार की एक रीढ़ है, मिथिला की राजधानी है, वहां 'दरभंगा एयरपोर्ट' देने का काम किया है। महोदय, अगर उनको यह विकास नहीं दिखता है, तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। आज़ादी के बाद सिर्फ 7 एम्स थे, उन 7 एम्स में 6 एम्स माननीय पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बने और अभी पूरे हिन्दुस्तान में 10 एम्स हैं, जिनमें 2 एम्स सिर्फ बिहार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देने का काम किया। अगर यह विकास कांग्रेसियों को और आरजेडी वालों को नहीं समझ आता है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है।

महोदय, बिहार को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए हाजीपुर से होते हुए एक राजेन्द्र सेतु पुल था, जो 1980 के दशक में बना था। उसके बाद उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए करोड़ों रुपये की लागत से माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में बक्सर गंगा ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। महोदय, अंग्रेजों के ज़माने से ही सोन नदी पर एकमात्र कोईलवर पुल हुआ करता था। हमारे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद वहां करोड़ों रुपये की लागत से कोईलवर का ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, अगर वह कांग्रेसियों को नहीं दिखता है, तो यह हमारी प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें अपने चश्मे का नंबर बदलवाने की ज़रूरत है।

महोदय, बेगूसराय को जोड़ने के लिए जो सिमरिया घाट है, जहां कुंभ की तरह अर्ध कुंभ का मेला लगता है, वहां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्मभूमि भी है। उनको जोड़ने के लिए सिर्फ एक राजेंद्र सेतु था, जो जर्जर स्थिति में था। अभी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में करोड़ों रुपये की लागत से मोकामा और बेगूसराय को जोड़ने के लिए – मोकामा से बेगूसराय पार करेंगे तो सीमांचल तक, नेपाल के बॉर्डर और बंगलादेश के बॉर्डर तक जाने के लिए ब्रिज बना है। अगर यह विपक्षियों को समझ में नहीं आता है कि यह बिहार का विकास है, तो इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है।

महोदय, मैं अपने प्रधान मंत्री जी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है। महोदय, मखाना जितना खाने में स्वादिष्ट है, जितनी पौष्टिकता उस मखाने में है, उसकी खेती करना उतना ही कठिन और मुश्किल भरा काम होता है। आज 'मखाना बोर्ड' बन जाने से मिथिला के हमारे लाखों किसानों को, लाखों मज़दूरों को, लाखों अति पिछड़ों और लाखों दलित समुदाय के लोगों को, जो मज़दूरी करते हैं, जो खेती करते हैं, उन सबको पूर्ण लाभ मिलेगा।

उनको उनके मखाना की लागत का उचित मूल्य मिलने की वजह से उनकी मजदूरी बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी, इससे जो हमारे मखाने के किसान हैं, उनका विकास होगा। विपक्ष ने कहा कि यह क्यों नहीं दिया गया, तो आप 50 साल से थे, आप मखाना बोर्ड बना देते, आप लीची बोर्ड बना देते! आपको किसी ने नहीं रोका था। आखिर में जो भी दिया, वह नरेन्द्र मोदी जी ने ही

दिया। आपने बिहार को नक्सलवाद, उग्रवाद, जातिवाद दिया, इसके अलावा आपने कुछ नहीं दिया। सर, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने बिहटा में शायद करोड़ों की लागत से, मैं एग्जेक्ट उसका मूल्य नहीं जानता हूं, लेकिन 600 बेड का ईएसआई हॉस्पिटल दिया। पटना, जो बिहार की राजधानी है, मुश्किल से वहां से 35 किलोमीटर पर है। आजादी के बाद से कोसी को कोई देखने वाला नहीं था। आज उस कोसी नदी पर कोसी महासेतु बना है, वह नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में बना है। अगर विपक्षियों को यह विकास नहीं दिखता है, तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप बहुत कुछ कह रहे हैं। आगे कहिए।

श्री शंभू शरण पटेल : सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप सही बोल रहे हैं, बोलते रहिए। आप बोलिए।

श्री शंभू शरण पटेल : सर, मेरा आग्रह है कि मेरा समय बढ़ा दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप बोलिए। जितना समय मिला है, उसमें तो बोलिए।

श्री शंभू शरण पटेल : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में मखाना बोर्ड के साथ-साथ पटना में आईआईटी देने का काम किया। मैं विपक्षियों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पटना को आईआईटी देने का काम क्यों नहीं किया था? आज आईआईटी, पटना का विस्तारीकरण करने के लिए वहां का जो छात्रावास है, उसको डेवलप करने के लिए उन्होंने इस बजट में प्रावधान किया है, तो हमारे विपक्ष के साथियों को बुरा लगता है। आज भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर वे देख नहीं पाते हैं, तो यह उनका कसूर है। हमारे नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में बिहार के लिए पैकेज देने का कार्य किया गया है, मैं उसके बारे में संक्षिप्त में अपनी सरकार की दस वर्षों की उपलब्धियों को बताना चाहूंगा। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में पटना में दो एम्स, आईआईटी, पटना, बिहटा में ईएसआई हॉस्पिटल, कोईलवर पुल, बिहटा से हाईवे, मोकामा से बेगूसराय जोड़ने के लिए करोड़ों की लागत से पुल, सिमरिया घाट का पुल, पटना और हाजीपुर को जोड़ने के लिए उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए तीन नए ब्रिज ...(**समय की घंटी**)... सर, मैंने अपने एमओएस से आग्रह किया है कि मुझे थोड़ा और समय दिया जाए। मैं पहली बार बजट पर बोल रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप समाप्त करें।

श्री शंभू शरण पटेल : सर, मुझे पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप समाप्त करें।

श्री शंभू शरण पटेल : सर, आप आगे किसी और भाषण में मेरा समय काट लीजिएगा। आप मुझे सिर्फ पांच मिनट बोलने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : यहां गुणा-भाग नहीं होता है। आप जल्दी अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री शंभू शरण पटेल : सर, हमारे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने गंगा ब्रिज पर चार नए पुल देने का काम किया है, जो उत्तर बिहार को जोड़ेगा। अगर यह सब विपक्ष को समझ में नहीं आता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे पांच मिनट इसलिए मांग रहा हूं ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप इतना कुछ कर रहे हैं।

श्री शंभू शरण पटेल : उन्होंने बिहार का बहुत अपमान किया है। एक काव्य के जरिए मैं अपने बिहार का बखान विपक्षियों को करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : वह आप अंत में काव्य के द्वारा ही कर दीजिए।

श्री शंभू शरण पटेल : जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों के नेताओं ने बिहार का उपहास किया है, जिस आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर 50 वर्षों तक शासन करने के बाद भी हमारे बिहार को विनाश की ओर ढकेला था, उस बिहार के बारे स्पेशल पैकेज देकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसको बढ़ाने का काम किया है, तो उन्होंने कहा कि यह बिहार का बजट है, बिहार का उपहास किया और आरजेडी वालों ने उसका सपोर्ट किया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं क्या हूं और बिहार क्या है?

"हां, मैं बिहार हूं।
मैं जनक जननी सीता मईया की जन्म स्थली
पुनौरा धाम हूं, सीतामढ़ी हूं, हां मैं बिहार हूं।
हां, मैं बिहार हूं,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का ससुराल हूं, हां मैं बिहार हूं।
गुरु विश्वामित्र जी की धरती और भगवान प्रभु श्रीराम और
लक्ष्मण जी की पहली पाठशाला बक्सर हूं, हां मैं बिहार हूं।
भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली हूं, हां मैं बिहार हूं।
*दुनिया को अहिंसा और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले"...(**व्यवधान**)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री शंभू शरण पटेल : सर, एक मिनट, प्लीज़। ...*(**व्यवधान**)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री शंभू शरण पटेल : सर, अभी मेरा 15 मिनट का समय पूरा नहीं हुआ है। आप मुझे बोलने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री शंभू शरण पटेल : उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक-दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष जी, बिना भेदभाव मानवता की रक्षा करने वाले सिख धर्म के दसवें धर्म गुरु, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री शंभू शरण पटेल : उपसभाध्यक्ष जी, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए। ...(**व्यवधान**)... आपका समय तो वैसे भी समाप्त हो गया है। राजीव शुक्ल जी, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

श्री राजीव शुक्ला (छत्तीसगढ़) **:** उपसभाध्यक्ष जी, बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शंभू शरण पटेल : उपसभाध्यक्ष जी, ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री राजीव शुक्ला : महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदया, निर्मला सीतारमण जी को इस बात की बधाई देता हूं कि वे आठवाँ बजट पेश कर रही हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री शंभू शरण पटेल : उपसभाध्यक्ष जी, बिहार के बारे में ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, बिहार के बारे में सब जानते हैं, आपका भाषण बहुत अच्छा था। आपका समय पूरा हो गया है, आप इधर ध्यान दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ला : महोदय, बजट क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि Budget is of the elections, by the elections and for the elections. यह चुनावी बजट है, यह 140 करोड़ भारतीयों का बजट नहीं है, यह भारत के भविष्य का बजट नहीं है, बल्कि यह उन राज्यों के लिए होता है, जहाँ या तो चुनाव हो रहे हों या होने वाले हों। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : शायद इसीलिए one nation-one election का विषय चल रहा है।

श्री राजीव शुक्ला : महोदय, वह प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे लागू करेंगे? जब तक पाँच साल तक हाउस डिज़ॉल्व न हो, जब तक उसका प्रोविज़न न हो, तब तक वह पॉसिबल नहीं है।

महोदय, मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली में चुनाव था, तो बजट में दिल्ली के बारे में घोषणा की गई है, बिहार में है, तो बिहार के बारे में घोषणा की गई है, लेकिन अगर बिहार की असलियत देखें - अखिलेश जी ने तो बताया है कि इसके पहले पाँच साल तक बिहार याद नहीं आया। ...(**व्यवधान**)...

श्री शंभू शरण पटेल : बिहार के बारे में ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ला : महोदय, क्या आपको पता है कि बिहार की पर कैपिटा इन्कम सबसे कम है? यह 60 हज़ार रुपये है, जबकि बाकी राज्यों की 70 हज़ार रुपये हैं। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए। पटेल साहब, आप स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। कविता पढ़ने से कुछ नहीं होता है, स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए। ...(**व्यवधान**)... हमने कारण बताए हैं, आप दस साल से बैठे हैं, आप दर्जा दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री शंभू शरण पटेल : महोदय ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ला : महोदय, इस टाइम को मेरे टाइम में जोड़ दीजिए, जिससे अगर ये टोका-टाकी करेंगे, तो मेरा टाइम कम न हो। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आपको टाइम दे देंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ला : महोदय, ये टोका-टाकी करेंगे, तो मेरा टाइम कम होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री शंभू शरण पटेल : महोदय ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : पटेल जी, आप विराजिए। आप कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री राजीव शुक्ला : महोदय, अगर बिहार की असली मदद करनी है, तो वहाँ की पर कैपिटा इन्कम बढ़ाइए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाइए, जीडीपी में उसका योगदान ज्यादा कीजिए। ...(**व्यवधान**)... अगर आप ऐसा करेंगे, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या यह कोई तरीका है कि आप बोलते चले जा रहे हैं? जब आप बोल रहे थे, तब क्या हम बोले थे? ...(**व्यवधान**)...आप नंबर बढ़ाने का काम मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : पटेल जी, कृपया आप विराजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ला : आप अपना एग्रेशन वहाँ पर दिखाइए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप विराजिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री अनिल कुमार यादव मंदादी (तेलंगाना)**:** आप क्या बात कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... आप किसकी धमकी दे रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आसन की बिना अनुमति के जो भी बोला गया है, वह अंकित नहीं किया जाएगा, सिर्फ राजीव शुक्ला जी बोलेंगे।

श्री राजीव शुक्ला : सर, उसका टाइम भी देख लीजिए।

This is not a fiscal policy; this is a political expediency. This is what I want to say. जब बेरोजगारी की बात आती है, तो हम पाते हैं कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है। यह CMIE के डेटा में कहा गया है। महोदय, यूथ, जो हमारी शक्ति होती थी - क्या आपको पता है कि इस देश की जो 60 प्रतिशत युवा शक्ति थी, उसके लिए सब जगह पर कहा जाता था कि भारत सबसे यंग देश है, भारत सबसे नौजवान देश है? लेकिन आज वह नौजवान कहाँ है? वह नौजवान आज गाँव में बैठा हुआ है। क्योंकि कोरोना के बाद जब वह गया, तो वापस लौटकर नहीं आया। आप देख लीजिए कि पंजाब में न कृषि के लिए मजदूर उपलब्ध हैं, न गुजरात के सूरत में जो डायमंड इंडस्ट्री है, उसके लिए मजदूर उपलब्ध हैं और न मैन्युफैक्चरिंग के लिए मजदूर उपलब्ध हैं।

मुंबई में हमारी लेबर कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सफर कर रहा है। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, इसलिए अल्टीमेटली हमारा एक्सपोर्ट सफर करता है। इस मामले में चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये आगे निकल जाते हैं। हम अपनी युवा शक्ति को कैसे वापस मैन्युफैक्चरिंग में ले जाएं, उन्हें छोटे-छोटे कल-कारखानों, उद्योगों में भेज सकें, यह होना चाहिए। जो हमारी युवा शक्ति बेकार बैठी है, निश्चित रूप से, हमें उसे कार्य देना चाहिए और रियल स्टेट सेक्टर और सब जगह पर उन्हें मौका देना चाहिए। अब मनरेगा का

एलोकेशन 33 परसेंट कम कर दिया गया है, जबकि गाँव में यह रोजगार का एकमात्र साधन है। वहाँ इसी से लोगों को रोजगार मिलता है और इसी से लोगों का पेट पलता है, लेकिन यह उस समय की मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसका 33 परसेंट एलोकेशन क्यों कम हुआ है? वह एक ऐसी स्कीम है, जो निश्चित रूप से ग्रामीणों को कर्ज से निकालती है, क्योंकि तमाम ग्रामीण कर्ज में डूबे हुए हैं और उन्हें इससे मदद पहुंचती है।

वेल्थ डिस्पेरिटी - एक प्रतिशत लोगों के पास 40 प्रतिशत धन है। यह जो accumulation of money है, इसका जितना ज्यादा विकेंद्रीकरण होगा, जितना लोगों में जाएगा, उतना अच्छा है। यह तभी हो सकता है, जब आप सबको अवसर मुहैया कराएं और उन्हें मौका दें। हमारी वित्त मंत्री जी से यह माँग है कि यह जो पूंजी का केंद्रीयकरण हो रहा है, वह रुकना चाहिए।

महंगाई के रिकॉर्ड के बारे में तो आपसे कहने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें कितना बुरा हाल है। हर चीज महंगी है। पेट्रोल-डीजल तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा खाने-पीने की सारी चीज बेइंतहा महंगी हैं। रिटेल इन्फ्लेशन 5.7 प्रतिशत है, जबकि लोगों की जो वेजेज़ बढ़ी है, वह 0.8 परसेंट से 5 परसेंट तक बढ़ी है। यह जो दोनों का गैप है, इसमें से लोगों को कैसे राहत मिलेगी, क्योंकि अगर महंगाई पर काबू नहीं किया गया -- यह वादा था कि महंगाई पर काबू करेंगे, लेकिन दाल हो, सब्जी हो, तेल हो, जितनी भी खाने-पीने की चीज़ें हैं या कपड़ा इत्यादि हैं, हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है कि उस महंगाई पर काबू नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हिडन टैक्स भी एक तरह से महंगाई है। आप आय कर में जितनी भी छूट देते हैं, दूसरे करों में छूट देते हैं, उसका भुगतान लोगों को महंगाई के जरिए करना पड़ता है। वह उतना बढ़ जाता है, तो उसका दाम देना पड़ता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

अब मैं फ्लैगशिप स्कीम पर आता हूँ। मैं योजना मंत्री भी था। प्रधान मंत्री आवास योजना के 25 प्रतिशत फंड यूटिलाइज ही नहीं हुए, उनका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। 2022 तक हरेक को छत देने का जो वादा था, वह नहीं पूरा हुआ। वादा तो लाल किले की प्राचीर से किया गया था, लेकिन आज तक वह वादा नहीं पूरा हुआ। ...(**व्यवधान**)... चार करोड़ तो हो सकता है, लेकिन 140 करोड़ लोगों के देश में चार करोड़ से क्या फर्क पड़ने वाला है? जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसमें एक्सपर्ट्स के सर्वे में बताया गया है कि 21 परसेंट रोड्स संतोषजनक स्थिति में नहीं पाए गए हैं। इसका मतलब कि उनके रख-रखाव, maintenance और बनाने की क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ग्रामीण सड़कें इस तरह से बनीं, तो हमें इसका बहुत भारी नुकसान होगा। ग्रामीण कौशल योजना - 2,369 ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए पैसे दिए गए, उन्हें बनाया गया, लेकिन काम सिर्फ 629 कर रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा फेलियर है, यह स्कीम बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है। फसल बीमा योजना में धन घटता चला जा रहा है। पहले किसानों को 29,000 करोड़ दिया जाता था, अब 16,000 करोड़ रह गया है। सर, एजुकेशन के बजट की बात करते हैं। देश में सबसे जरूरी तो शिक्षा है। अगर हमने युवाओं को नहीं पढ़ाया, आज की जेनरेशन को नहीं पढ़ाया, इस पीढ़ी को नहीं पढ़ाया, तो आगे कैसे तरक्की करेंगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर विदेश में कैसे नाम करेंगे। जीडीपी का सिर्फ चार परसेंट बजट एजुकेशन के लिए है। मेरे ख्याल से शिक्षा के लिए यह बहुत कम अमाउंट है। इसे बढ़ाना चाहिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। वित्त मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना होगा। पब्लिक हेल्थ केयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोविड हुआ, तो कोविड के समय में लोगों को समझ में आया कि हमारे अस्पताल, हमारे

equipments, हमारी दवाएं, यह सब बहुत बढ़िया होना चाहिए। देश में उस समय व्यक्ति के पास कितना भी पैसा था, उसके हाथ में कुछ नहीं रह गया था।

लोग एक-एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाखों रुपये देने को तैयार थे, लेकिन वह नहीं मिल रहा था, तो उस समय लोगों की समझ में आया कि हमारा पब्लिक हैल्थ केयर सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए। यह दुख की बात है कि उसके लिए बजट में प्रावधान 2 परसेंट से नीचे है। यह बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पब्लिक हेल्थ केयर के लिए एक लंबा चौड़ा बजट दिया जाना चाहिए। हम कोरोना से भी सबक नहीं ले पाए और इसके लिए बजट 2 परसेंट से नीचे ही है।

आरएंडडी का बजट - शोध सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम शोध नहीं करेंगे, नई-नई चीजें नहीं निकालेंगे और पश्चिमी देशों के भरोसे रहेंगे, तो हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। अगर हम शोध नहीं करेंगे, तो विकसित भारत नहीं बन सकता है। हमें रिसर्च पर सबसे ज्यादा खर्च करना चाहिए। इस पर चीन 2.4 प्रतिशत खर्च करता है। दक्षिण कोरिया जैसा देश भी 4.5 प्रतिशत खर्च करता है, लेकिन हम इस पर 0.7 परसेंट खर्च करते हैं, जो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मूंगफली के बराबर है। सरकार को इस तरफ भी देखना होगा। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक बात का जिक्र आज सुबह सोनिया जी ने किया कि जो फूड फॉर सिक्योरिटी है, जिसके जरिए लोगों को गांव में मुफ्त राशन वगैरह दिया जा रहा है, वह मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी, कांग्रेस सरकार की योजना थी। अच्छा है कि उसको लागू किया गया, लेकिन 2011 का हमारा जो सेंसस था, जो जनगणना थी, वह उसके आधार पर था। इससे कम से कम 5 करोड़ लोग वंचित हैं। जनगणना कराई जानी चाहिए और वंचित लोगों को इसका लाभ मिले, तो बहुत अच्छा होगा। यह बात आज सोनिया जी ने सुबह उठाई थी, मैं भी इसे दोबारा इसमें रखना चाहता हूं। एक बड़े अर्थशास्त्री हैं - रुचिर शर्मा। अभी हाल में उनकी पुस्तक आई है और उन्होंने कहा भी है कि इस देश में उद्यमियों, उद्योगों और व्यापार को जो छूट मिलनी चाहिए, जो फ्रीडम मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके ऊपर सरकारी एजेंसियों का इतना दबाव है कि वह आदमी चाहे जीएसटी देने वाला हो, चाहे इनकम टैक्स देने वाला हो, चाहे अन्य कोई हो, उसे ईज़ ऑफ बिजनेस, व्यापार में आसानी नहीं लग रही। इस बात को दोनों तरफ के लोग अनुभव करते हैं कि व्यापार में सब डरे रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कम से कम एक लाख उद्यमी और व्यापारी नागरिकता छोड़ चुके हैं और हजारों लोग भारत छोड़कर दुबई और अन्य जगहों पर जाकर बस गए हैं। जब एक उद्यमी जाता है, तो लाखों लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि वह बहुत लोगों को रोजगार देता है। अगर वह चला जाता है, तो रोजगार चला जाता है। वह विदेशों में जाकर रोजगार ले रहा है और वहां के लोगों को रोजगार दे रहा है। यहां वह सरकारी एजेंसियों से इतना डरा हुआ है कि वह यहां से भाग जाता है। बिजनेस की फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए। यह बात रुचिर शर्मा ने भारत के लिए अपनी बुक में वर्ल्डवाइड कही है।

इन्होंने एयर फेयर का भी जिक्र किया कि किस तरह से विमानों के किराए वगैरह पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं। यह ठीक है कि आज कोई सरकारी एयरलाइंस नहीं रही, सारी एयरलाइंस प्राइवेटाइज हो गई हैं, लेकिन इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए कि अनाप-शनाप किराया न लिया जाए और कुछ इस तरह की व्यवस्था करें, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके।

एक बहुत बड़ी चीज है - डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती स्थिति। आपको पता है कि आदरणीय मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी का कितना मजाक बनाया था कि रुपये की ऐसी स्थिति

है कि वह प्रधान मंत्री की उम्र पार कर गया है, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज यह 87, 88 रुपये पर पहुंच गया है और किसी भी समय 90 रुपये पर भी पहुंच सकता है। यह मजाक का विषय नहीं है। जिस तरह से रुपए की स्थिति गिर रही है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लोग निकालकर ले जा रहे हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व है, वह बिलियंस ऑफ डॉलर में गिर रहा है। रुपए में गिरावट को रोकने के लिए आपको काफी पैसा डालना पड़ता है। वह बिलियन डॉलर्स हमारे फॉरेक्स रिजर्व से, जो विदेशी मुंद्रा भंडार है, उससे कम होता चला जा रहा है। हमें इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि रुपया कैसे मजबूत रहे। यह ठीक है कि आप यह करते हैं, उससे एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा, लेकिन आज की स्थिति में हमारा एक्सपोर्ट तो डाउन जा रहा है। उसमें वह स्थिति नहीं रह गई है।

जीएसटी के संबंध में आप भी जानते हैं। राजस्थान आदि जगह में भी देखते हैं। जब यह कर आया था, तो लोगों को लगा था कि बहुत बड़ी आजादी मिलेगी। इसीलिए 1947 की तरह, आपको याद होगा कि सेंट्रल हॉल में फंक्शन किया गया था कि आज कर से आजादी मिली है, देश आजाद हुआ है, लेकिन जीएसटी से हर व्यापारी परेशान है, हर उद्योगपति परेशान है, छोटे-छोटे उद्योग वाले परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं। जीएसटी के लोग उनको बहुत तंग करते हैं और अनाप-शनाप जीएसटी लगा देते हैं। उसका वह प्रावधान तो सबसे खराब है कि आप सरकार में कोई काम करते हैं, तो जिस दिन आपने बिल रेज किया, जिस दिन बिल लगाया, उस दिन ही वे जीएसटी काट लेते हैं और गवर्नमेंट से पेमेंट साल भर बाद आता है।

7.00 P.M.

आप सोचिए कि आदमी को लोन ले-ले कर जीएसटी देना पड़ रहा है। इस चीज पर भी माननीया वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। मैं सुझाव सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि कैसे वे इससे राहत दे सकें और इस समस्या का समाधान हो सके।

सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। आज तक न उस पर चर्चा हुई और न ही उस पर कोई बात हो रही है। उस मामले में सरकार को व्हाइट पेपर लाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, उस तरह से सारी बातें और तथ्य जनता के सामने रखनी चाहिए, जो हम नहीं रख पा रहे हैं।

अगर हम जीएसटी के मामले में कहें, माननीया वित्त मंत्री जी यहाँ नहीं है, तो अब जैसे पॉपकॉर्न को लेकर जो प्रावधान है, जो मक्के की चीज है, पॉपकॉर्न के बारे में आप देखिए कि वे कह रही हैं कि जो नमकीन पॉपकार्न है, उस पर 5 परसेंट जीएसटी और जो मीठा पॉपकार्न है, उस पर 18 परसेंट जीएसटी लगेगा। लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा है कि पॉपकॉर्न पर दो जीएसटी कैसे हो सकते हैं! इसको तो आम लोग खाते हैं। सब जगह आज के युवा, बच्चे, सारे लोग, चाहे स्कूल के हों, कॉलेज के हों, सब पॉपकार्न खाते हैं। इस बात का कितना मजाक उड़ता है! यह देखना चाहिए कि आप पैरिटी, समानता कैसे लाएँ। अगर आप एक ही प्रोडक्ट पर दो जीएसटी उतने फर्क के साथ लगाएँगी, तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।

कुल मिला कर मैं यही कहूँगा कि यह बजट युवा, किसान, महिलाओं, व्यापारी और बेरोजगारों के लिए नहीं है, बल्कि बैलेट बॉक्स और वोट बैंक के लिए है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद, शुक्ला जी। Next speaker, Shri Manas Ranjan Mangaraj to speak in Odia. You have three minutes' time.

SHRI MANAS RANJAN MANGARAJ (Odisha): [&] "There is a proverb in Odia— *"Speech is admirable if one knows how to speak it well."* This implies that even the most insignificant things can gain attention and can be popularized if you master in the art of distorting it. The 2025-26 Budget, presented by the Finance Minister in Parliament, is similarly a collection of minor and insignificant provisions. There is no inconsistency in calling this Budget a *"Bihar Budget"* instead of a Budget for the entire country. The Finance Minister seems to have forgotten that India comprises many other States and Union Territories besides Bihar.

We are not against providing special grants and assistance to any State. However, in a federal structure, states like Odisha are equally entitled to such benefits. The Finance Minister spoke about Bihar alone for three minutes out of her 77-minute speech, mentioning the State nine times. But are other States—Odisha, West Bengal, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, and Maharashtra—not part of India? Six months ago, in the 2024 budget, Bihar was granted a special assistance package of ₹59,000 crore. Andhra Pradesh received a special package for Polavaram. However, Odisha received nothing then, and once again, nothing has been announced for the state in this budget.

The BJD, under former Chief Minister Naveen Patnaik, has been demanding special category status for disaster-prone Odisha. Yet, Odisha neither enjoys this status nor receives special assistance. Revenue generated from Odisha's mineral resources is being utilized in other States. Odisha's coal powers the nation, but despite the Central Government collecting ₹10,000 crore annually from Odisha under the *Green Cess*, not a single penny is allocated for the development of coal mining-affected areas in the State.

The Union Budget makes no significant provisions for agricultural production, income growth, rural employment, nutritional assistance, inflation control, or debt relief for farmers. The Government has remained silent on farmers' long-standing demand for a legal guarantee on minimum support prices (MSP) for crops. The increase in the KCC loan limit from ₹3 lakh to ₹5 lakh appears to be aimed more at sustaining the corporate sector's sale of expensive agricultural goods rather than genuinely boosting economic growth.

[&] English translation of the original speech delivered in Odia.

The Rural Development budget has increased by just ₹1 crore compared to the previous year. For agriculture and allied sectors, the increase is merely ₹20,000 crore. Ironically, the food subsidy has been reduced from ₹2.5 lakh crore in the last budget to ₹2.3 lakh crore this year. How can such a budget benefit the people?

The Central Government's contribution to the monthly allowance for crores of elderly, widows, and disabled individuals has remained stagnant at ₹200 since 2006. It is regrettable that this Budget offers no increase in that amount.

While the Government dreams of a five trillion dollar economy, the rupee has hit an all-time low. At the time of independence, the value of the rupee and the dollar were nearly the same; today, the exchange rate has touched ₹88 per dollar. India's ranking on the *Happiness Index* continues to decline, and the strength of the Indian passport weakens each year. What kind of growth is this?

The Finance Minister announced tax exemptions for individuals earning up to ₹12 lakh. However, when employment opportunities remain elusive, such a rebate is merely pleasing to the ears—it offers little real benefit to the youth."

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। आपका समय समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, वैसे भी संसदीय परंपरा में पढ़ना allowed नहीं है, पर मैंने आपको allow कर रखा है। आप कृपया बैठ जाएँ, आपका भाषण समाप्त हुआ।

SHRI MANAS RANJAN MANGARAJ : Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद। श्री संजय कुमार झा।

श्री संजय कुमार झा (बिहार) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया है।

महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो आदरणीया वित्त मंत्री जी ने कर में जो छूट दिया, उससे निश्चित रूप से 1,75,000 करदाताओं को फायदा होगा और उन्होंने जो एक लाख करोड़ रुपये छोड़े हैं, यह उन लोगों की बचत होगी। हमारे एक साथी यहाँ पर यह अपेक्षा करते हुए ठीक ही बोल रहे थे कि जब लोगों का वह पैसा मार्केट में जाएगा, तो यह consumption में, saving में और investment में काम आएगा। जब आप मार्केट में जाकर पैसा खर्च करते हैं, तो उसके बाद वह chain develop होता है। इससे productivity भी होगी, manufacturing भी होगी और मार्केट भी चलेगा। वह यहीं पर खर्च करे, यह अपेक्षा जरूर की गई होगी। उसी तरह मैं TDS, TCS देख रहा था। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो इनकम टैक्स रिफंड है, वह एक दिन में, दो दिन में आ जाता है, 48 घंटे में आ जाता है। उसे faceless कर दिया गया है और इसमें टेक्नोलॉजी को use किया गया है। इन सब चीजों से परिस्थितियाँ काफी बदली हैं।

मैं एक और क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। हमारे मंत्री माँझी जी यहां बैठे हुए हैं। इनके MSMEs में भी बहुत सारे issues को address किया गया है, जिसमें credit access regulatory simplification है, physical and digital infrastructure में सुधार के लिए काम किया गया है और यह देश एक manufacturing hub बने, global manufacturing hub बने, उस पर काम किया गया है। इस बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन लॉन्च किया गया है और अगले 4 सालों तक किसानों से दलहन की केंद्रीय खरीद की जाएगी। बिहार जैसे प्रदेश में, जहां मोकामा टाल वगैरह में दलहन की खेती होती है, वहाँ निश्चित रूप से दलहन के उत्पादन बढ़ने से इसका लाभ मिलेगा।

एग्रीकल्चर सेक्टर में एक और काम यह किया गया है कि जो 100 low productivity वाले जिले हैं, उनको adopt करने का काम किया गया है। ऐसे 100 districts को चुना गया है, जहां उपज कम होती है। वहाँ crop diversification करके, production बढ़ाने हेतु उनको चुना गया है। उसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना का नवीकरण किया गया है, जिसमें street vendors को 30,000 की सीमा में UPI linked credit card और बैंक लोन मिलेगा। जो gig workers है, जो ऊबर, ओला, जोमैटो आदि में काम करते हैं, उनकी संख्या करीब 1 करोड़ है। उनको आयुष्मान भारत और हेल्थ इंश्योरेंस के तहत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ का मिले, इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है।

हम लोग देखते हैं कि अभी कोरोना हुआ, यूक्रेन में वॉर हुआ। वहाँ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए थे। यहाँ इसकी बहुत डिमांड है, इसलिए मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अगले 1 साल में 10,000 और अगले 5 सालों में 75,000 सीट्स बढ़ाने की बात इस बजट में आई है। उसी तरह urban infrastructure के लिए जो challanges हैं, उनके लिए स्पेशल फंड दिया गया है। इस बार तो दिल्ली के चुनाव में हम लोग देख रहे थे कि दिल्ली की कॉलोनियों में रोड और पानी का किस तरह का हाल था। उस चीज के लिए पूरे देश के लिए प्रावधान किया गया है। उसी तरह जहाँ तक मुझे मालूम है, nuclear energy के लिए भी सरकार ने 20,000 करोड़ का बजट दिया है।

महोदय, मैं एक बात यह कहूंगा कि बजट में जो जनरल चीजें हाईलाइट करने वाली थीं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के हमारे एक साथी बता रहे थे कि बिहार को historically neglect किया गया। महोदय, जब झारखंड भी बिहार के साथ था, तब freight equalisation था। झारखंड के सारे मिनरल्स पूरे देश में जाते थे, लेकिन उसका कोई भी advantage बिहार को नहीं मिला। बिहार की हमेशा यह डिमांड रही, जोकि एक सही बात है कि उसे विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने यह बात खत्म कर दी और हमारी पार्टी तथा हमारे नेता, नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, तो बिहार को विशेष पैकेज मिले। हम आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पिछले बजट में भी बिहार के flood को address किया, जबकि पहले वह कभी address नहीं हुआ था और वहाँ कोसी का flood आता रहा। मैं जिस एरिया से आता हूँ, वह मिथिला एरिया है। वहाँ हम हर साल flood देखते रहे।

हमेशा यह होता था कि नेपाल में हाईडैम बन रहा है, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने नॉर्थ-बिहार के मिथिला के फ्लड को भी एड्रेस किया है। आज मखाना की चर्चा दुनिया में हो रही है, जबकि मखाना का प्रोडक्शन तो हमेशा से होता रहा है, लेकिन पहली बार वहाँ मखाना बोर्ड बनेगा। मखाना की उत्पादन बिहार में होता था, लेकिन उसकी पैकेजिंग बेंगलुरु में होती थी। अब वहाँ पर ही पैकेजिंग होगी, मार्केट लिंकेज होगा। दरभंगा में एयरपोर्ट है और पूर्णिया में भी एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, उसके माध्यम से कार्गो की व्यवस्था होगी। इससे वहां के लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा। इसी तरह से बिहार के लिए और एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। पूरी दुनिया बिहार का diaspora है और खास करके गल्फ कंट्रीज वगैरह में वहां के लोग रहते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल फ्लाइट बिहार से नहीं चलती है। वित्त मंत्री जी ने तीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की जो घोषणा की है, उनमें से एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, वह पटना के बगल में होगा। वह एयरपोर्ट बनने से निश्चित रूप से इंटरनेशनल फ्लाइट भी बिहार से जानी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, वह वेस्टर्न कोसी योजना का है। 1972 से उसका डीपीआर बन कर प्रोजेक्ट चल रहा था, 53 साल, हम लोग तो पैदा ही हुए थे। पूरे उत्तर बिहार की सिंचाई को लेकर वेस्टर्न कोसी योजना बनी थी, लेकिन वह आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। हम वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने भाषण में मिथिला का भी नाम लिया और वेस्टर्न कोसी प्रोजेक्ट को भारत सरकार सैंक्शन करके उस पर काम करना शुरू करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के बजट में वे खुद भी मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन कर आईं। कम-से-कम उस पेंटिंग से जुड़े हुए मिथिला के जो लोग हैं, जो देश और दुनिया में हैं, उन सबके लिए यह एक प्रतिष्ठा की बात हुई कि वित्त मंत्री जी ने जब अपना बजट पढ़ा, तो उसमें इसका ध्यान रखा। मुझे लगता है कि बिहार कभी भी फोकस में नहीं आया। अभी हम देख रहे थे कि बिहार में चार एग्रीकल्चर रोड मैप में काम हुआ है और कृषि में वहां पर रिवॉल्यूशन आया है। अभी सब्जी के उत्पादन में बिहार देश में चौथे नंबर पर आया है। बहुत सारा काम बिहार में पिछले 17, 18, 19 सालों में हुआ है। बिहार टेक ऑफ स्टेज में है। जो डेटा यहां पढ़ा जा रहा था, वह सही है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोगों ने कांग्रेस और आरजेडी से जो inherit किया, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि हम लोग शुरू कहां से किए थे। हम लोगों को बिहार में क्या मिला था, जब हम लोग सरकार में आए थे। आज हम लोग कहां से कहां ट्रेवल किए। बिहार टेक ऑफ स्टेज में है। पहली बार बिहार भी डबल इंजन का मजा ले रहा है। केन्द्र का जो विशेष ध्यान बिहार के ऊपर है, उससे हम लोगों को लगता है कि निश्चित रूप से अगले 5 साल में बिहार भी टॉप टेन स्टेट में आएगा। दोनों बजट, पिछला बजट भी और इस बार के बजट में भी केंद्र सरकार का और आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का पूर्वोदय का एक परिकल्पना है कि जब तक पूरब के स्टेट्स मेन लिंक में नहीं आएंगे, तब तक विकसित भारत का जो सपना है, वह पूरा नहीं हो पाएगा। उनका बिहार पर जो विशेष ध्यान गया है, इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में, बिहार के लोग वैसे भी मेहनती हैं, बिहार भी टॉप टेन स्टेट में आएगा। महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I genuinely believe that this is a visionary, historic, forward-looking and futuristic Budget. These are not empty, vague words. I will justify over the next 10-12 minutes why I believe so. Hon. Finance Minister has focused on women, youth and other marginalized groups by removing barriers to credit, technologies, skilling and other things. I compliment her and hon. Prime Minister for laying the road map for a five trillion dollar economy. Some of the hon. Members who spoke previously kept on harping, 'कैसे बनेगा 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी'। This is basic common sense. With a base of 4 trillion dollar economy, if you grow at 6.4 per cent which we are doing today, then, over 3-4 years, we will, definitely, become a 5 trillion dollar economy. And by 2047, we will become a 30 trillion dollar economy and *Viksit Bharat*.

Sir, reference was made to a particular railway project - Khurda- Balangir Railway Line. But conveniently, what was not mentioned was that the project started in 1974. सर, उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और उस समय अश्विनी वैष्णव जी भी रेल मंत्री नहीं थे, वे तो 2021 में रेल मंत्री बने हैं तथा प्रधान मंत्री भी नरेन्द्र मोदी जी नहीं थे, वे तो 2014 में प्रधान मंत्री बने हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह 40 सालों तक क्यों नहीं बना?

Sir, today, almost 256 kilometres of that particular railway line of 304 kilometres is complete. वह 80 परसेंट से ज्यादा कम्प्लीट हो चुकी है, जो इस सदन में बताया नहीं गया है। Sir, one incorrect statement was also made that the allocation for Odisha railway in the Budget has reduced over the last year. It is incorrect. This year, the Budget allocation for Odisha railway is Rs. 10,600 crore; in the last financial year, 2024-25, it was Rs.10,536 crore. सर, यह दो साल का बच्चा भी बता देगा कि 600 मैथेमैटिक्स में 536 से ज्यादा होता है। But this incorrect statement was made just for cheap publicity.

Sir, now, I will come to the substantial part of the Budget. No Member has spoken about sports. I believe that every one of us will be interested in sports. At Rs. 3,794 crore, this is the highest ever allocation to sports and we must compliment the hon. Finance Minister for this. She has never got a due, which shows that she has been focusing on sports. When Prime Minister Modiji talks about hosting or aspiring to host the Olympics in 2036, we need to focus on sports and we need to allocate more. Actually, I would request hon. Finance Minister to allocate, at least, Rs. 10,000 crore to sports. One data is pertinent here. I do not want to make this a 2013-14 *versus* 2025-26 thing, but this is interesting. An amount of only Rs.1,219 crore ही वर्ष 2013-14 में sports के लिए allocate किया गया था, जो इस बार 3,800 करोड़ के आसपास है, almost 3.1 times. This should be remembered. I will urge the Government to nudge the private sector to invest in sports as it is done in other countries. सर, यहां पर प्राइवेट सेक्टर sports में खर्च नहीं करता है। The Government should motivate them to spend. Then comes green growth. In this august House, there are many Members,

including Shri Jairam Ramesh and other Members, who are passionate about climate change, environment and sustainability issues. But the hon. Prime Minister has walked the talk by hiking the Budget for MNRE from BE of Rs. 19,100 crore in last year to Rs. 25,600 crore; it is a hike of almost 39 per cent. सर, बोलना एक बात है, लेकिन करके दिखाना दूसरी बात है। Renewable Energy Department को 25,600 करोड़ की लागत से 40 परसेंट hike किया गया है।

Sir, then, there is the Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Imagine one crore household getting free electricity, up to 300 units through this! This is going to save them almost Rs. 15,000 to Rs. 18,000 annually. उनकी साल की 15,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये की बचत हो रही है from this Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Then there is the National Green Hydrogen Mission. Again, it is something related to sustainability and green growth. The Budget has been hiked from Rs. 300 crore at RE last year to Rs. 600 crore in BE of this year.

सर, वित्त मंत्री जी ने EV के बारे में बात की। Basic customs duty on EV components has been brought down so that EVs become cheaper and affordable to a large section of people. Then comes R&D. This is the sixth time I am speaking on the Budget from 2020 and every time मैं R&D की बात करता हूँ। At 0.75 per cent of our GDP, we are one of the worst spenders on R&D in the world. सर, मैं यहां पर comparable numbers दूंगा। चाइना का खर्च 2.2 है, यूएस 3.2 खर्च करता है, साउथ कोरिया 4.5 खर्च करता है, Israel spends 5.6 per cent of its GDP on R&D, जबकि हम लोग दुनिया में सबसे कम खर्च करते हैं। World average is 1.8 per cent. सर, प्रधान मंत्री जी ने "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान" का जो स्लोगन दिया था, उसे उन्होंने पूरा करके दिखाया। Now, in this Budget, following the letter and spirit of what the hon. Prime Minister said, hon. Finance Minister made an announcement for 50,000 Atal Tinkering Labs in our Government schools in the next five years. सर, वहीं से curiosity develop होती है, वहीं से innovation आता है। Broadband connectivity has been assured to all Government secondary schools. सर, यह सोचिए कि अगर देश के हर सरकारी स्कूल में broadband connectivity हो जाएगी, then what will be the future of our country?

Sir, then comes the Centre of Excellence in AI. This is the age of AI and Centre of Excellence in AI for education has an outlay of Rs. 500 crore. An amount of Rs. 20,000 crore has been allocated for private sector driven R&D. These are extremely, extremely laudable announcements in the Budget. Then comes Startups. We all know that the hon. Prime Minister has been a great votary of Startups, and we are the third largest Startup hub with almost 1.6 lakh registered Startups in Startup India Initiative. In the State of Odisha, where I come from, there are almost 2,500 Startups, of which 50 per cent have been started by women. Again, the focus on Startup was clearly there in this Budget. A deep tech-focussed Fund of Funds was announced. A

new scheme was announced for five lakh women, SC and ST entrepreneurs where they can avail term loan up to Rs. 2 crore during the next five years.

सर, 5 लाख ऐसी महिलाएं और हमारे एससी/एसटी भाई-बहन हैं, जो स्टार्टअप्स करते हैं, जो entrepreneurs हैं। उनको अगले पांच साल में दो करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है। Finally, about tax exemption. I work a lot with Startups. सर, सारे स्टार्टअप्स ने बोला था कि यह जो tax exemption था, यह 31 मार्च, 2025 को खत्म हो जाएगा। कृपया करके इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। I am so glad and thank the hon. Finance Minister कि उसको 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे स्टार्टअप कल्चर और ज्यादा होगा। सर, Gig workers के बारे में बात की गई थी। सर, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से there are ten million (1 crore) Gig workers in the country. By 2029, there will be 23 million means 2.3 crore Gig workers in the country. Gig workers, provide employment and they also help in bringing gender parity. सर, जो Gig sector है, इसमें बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं, and because of the flexible working hours, women find it convenient to work in the Gig sector. By supporting Gig sector in the Budget, hon. Finance Minister has shown that this Government is for gender parity, for women empowerment and for job creation. She announced ID Cards & registration on the e-Shram portal for the Gig workers. All the Gig workers will be enrolled under the *Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana* which is going to help one crore Gig workers.

Now, defence is another area in which I am very interested. Many Parliamentary Standing Committees have recommended that we should spend, at least, 3 per cent of our GDP on Defence. It has not happened yet. We are still at 2 per cent. Today, our spending on Defence is almost 80 billion dollars. The exact number is Rs. 6.81 lakh crore. China spends about 300 billion dollars. It is almost four times of ours. We know as to what kind of relationship we have with China. Every time, I have been speaking that we should spend more on Defence, and I must thank the hon. Finance Minister that she has hiked the Defence Budget this year by 6.3 per cent over last year's BE. Regarding the export of Defence products, now, we are exporting Rs. 21,000 crore worth of Defence products which will grow to almost Rs. 50,000 crore over the next three-four years. I could go on and on.

Regarding Education and Healthcare, आईआईटी की सीट्स बढ़ाई जाएंगी, मेडिकल कॉलेजेज़ की सीट्स 7,500 over the next five years. Setting up of Day Care Cancer Centres in all district headquarter hospitals. We all know and everyone in this whole August House has a family member or a friend who has cancer. How difficult it is to go to Tata Memorial, Mumbai or any city hospital to get cancer treatment? Now, with these Day Care Cancer Centres in district hospitals, it will be great boon for small towns in India and rural India. On 36 life saving drugs, Basic Custom Duty has been reduced which will help millions of our patients.

Finally, I will come to my State of Odisha. I applaud the hon. Finance Minister when she announced a Mission for Cotton productivity. I come from Kalahandi District —just one or two minutes, Sir—which is known for its black cotton soil. We have one of the finest black cotton soils in the country and I had, in the past also, during the Zero Hour, requested the Government to set-up a Cotton Research Institute in Kalahandi. Now, again, I will request the Government to consider this.

Hon. Finance Minister also announced five National Centres of Excellence for Skilling. What a wonderful announcement! I request the Government that one of the centres should be set up in the State of Odisha, preferably, in Western Odisha. Regarding Tourism, in the last Budget, hon. Finance Minister had acknowledged Odisha's abundant tourism potential. Through you, I have a couple of suggestions. One is of Bali Yatra which is declared as a national festival. Then, Dhanu Yatra which is the largest open air theatre on Earth and, for 11 days, one town called Bargarh becomes Mathura *Nagri*. That should be considered for intangible cultural site of UNESCO.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, I will take 30 seconds. Finally, Sir, about Railways. During the UPA regime, between 2004 to 2014, ओडिशा को 734 करोड़ रुपये सालाना मिलते थे। Today, it is ten times more per year. This year has been Rs. 10,600 crore. 10 गुना ज्यादा मिल रहा है। आज ओडिशा की railway density 20 है, neighboring State में 48 है, पश्चिमी बंगाल में...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुजीत कुमार : सर, इसके लिए अश्विनी वैष्णव जी ज़िम्मेदार नहीं है, इसके लिए निर्मला सीतारमण जी ज़िम्मेदार नहीं हैं, this is past legacy. पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, तभी यह legacy आई, जिसे अब सुधारा जा रहा है। Finally, Madam Finance Minister...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद।

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, just last point. We should acknowledge the reality. When we demand more funds, is this enough? No! I do not think so. As a Member from Odisha, I definitely expect more funding from the Government. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri Vivek K. Tankha.

श्री विवेक के. तन्खा (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस वक्त जब बोलने के लिए निमंत्रण मिलता है, तो ऐसा लगता है that you are like a night watchman, जैसे क्रिकेट में होता है कि लास्ट में मौका मिलता है। Anyway, let me do the best.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप तो अच्छे batter हो, आप night watchman कैसे हो सकते हैं!

श्री विवेक के. तन्खा : सर, यह स्पीच विवेक तन्खा की नहीं है, यह स्पीच है देश के करोड़ों युवकों की, यह स्पीच है देश के सवा करोड़ गरीबों की, यह स्पीच है देश के लाखों मरीजों की और यह स्पीच है देश के करोड़ों श्रृद्धालुओं की,जो हर बजट को बहुत उम्मीद और आशा से देखते हैं। बजट coming year की income, expenditure and expected expenditure का एक लेखा-जोखा होता है। हमें बार-बार यह बताया जा रहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य, जो 2047 तक हासिल होगा, as if, यह बजट उस 'विकसित भारत' का बजट है। यह बजट तो एक साल का बजट है। हमें तो यह भी नहीं पता कि चार साल बाद क्या व्यवस्था होगी। इसी चुनाव में अगर बीस सीटें कम हो जातीं, तो कुछ दूसरी व्यवस्था हो सकती थी। मेरा यह कहना है कि बजट को annual feature मान कर उस साल के बारे में हम बात करें। हम आज कुंभ के बारे में बात करना चाहते हैं। बारह साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। बारह सालों के बजट में आपने उस कुंभ के लिए क्या प्रावधान किया? वहां 300 किलोमीटर की कतार है। वहां घुसना मुश्किल है । एयरपोर्ट से कुंभ एरिया में पहुंचने में difficulty है। Where is that infrastructure? आप जो infrastructure की बात कर रहे हैं, where is that infrastructure? जो कुछ भी आपने बनाया है, it is cosmetics. मेरा तो यह कहना है कि अगर धार्मिक पर्यटन, जिससे दो लाख करोड़ से ज्यादा की आमदनी होने वाली है, उन लोगों की व्यथा तो देखिए कि उनकी क्या हालत है? कोई planning नहीं है, कोई infrastructure नहीं है । आपको तैयारी के लिए बारह साल का समय मिला था। हमने इन 12 सालों में क्या किया? मेरा तो कहना है कि वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, नर्मदा, जबलपुर, केदारनाथ, वैष्णो देवी ये सभी प्राचीन और धार्मिक शहर हैं। ऐसी समस्या सब जगह उठती हैं। हमारे जो repeated Budgets आए हैं, उसमें इन शहरों के बारे में और ऐसे बड़े-बड़े आयोजनों के बारे में क्या सोचा गया, उसके लिए क्या प्रावधान हैं? मुझे तो कुछ खास नहीं दिखता है। मिशन आत्मनिर्भर भारत, pulses के बारे में आपने बोला, The aim is to reduce import dependency. Financial year 2024 में pulses का आयात hit a six-year high, surging by 84 per cent. India is the largest vegetable oil importer. हम जो vegetable oil का import करते हैं, fulfilling 70 per cent of its demand from foreign sources. Without investment in research and high-yielding seeds, such announcements remain a mere slogan. मुझे खुशी हुई कि मखाना बोर्ड, बिहार का एक unique initiative है, but आज USA मखाना का एक super market बन चुका है। जो हमारे farmers हैं, उनको तो मखाना की MSP तक नहीं मिलती है और जो profits होते हैं, वे सब बाहर जाते हैं। आपके पास जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं पर तो बजट का allocation होना चाहिए। इसी तरह मैं आपको MSMEs के बारे में बताना चाहता

हूं। MSMEs contribute 30 per cent to GDP and 45 per cent to exports. आप कहते हैं कि हमने credit guarantee to MSMEs बहुत increase की हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 19,828 MSMEs 2023-24 में shut down हुए हैं। अगर पिछले एक साल में बीस हजार MSMEs बंद हो रही हैं, तो इसकी क्या कहानी है। हम किस कहानी की बात कर रहे हैं। Is the support reaching the right beneficiaries? This is the question. इसी तरह fiscal target के बारे में बात की कि 4.4 per cent of the GDP कर रहे हैं down from 4.8 last year. अब आप Deficit reduction तो कर रहे हैं at the cost of massive cuts, but in what? Capital expenditure. आपने Education को 11,584 करोड़ रुपये से कम किया। आपने social welfare को 11,900 से reduce किया।

आपने रूरल डेवलपमेंट को 75 हज़ार करोड़ रुपये से रिड्यूस किया, एग्रिकल्चर को 10,992 करोड़ रुपये से रिड्यूस किया। इस सबका क्या मतलब है? अगर आपने डेफिसिट कम भी किया, पर इन सब चीज़ों को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया, तो आपने मेन टैक्सेस को अनएड्रेस छोड़ दिया।

महोदय, अब मैं टैक्सेशन की बात करता हूं। World में progressive taxation policies होती हैं। Indirect taxes contribute 27 per cent of gross receipts. Contribution of income tax is 22 per cent, जबकि income tax indirect tax से ज्यादा होना चाहिए, अगर हम country में equity की बात कर रहे हैं। Contribution of corporate tax is just 17 per cent, जिसको सबसे ज्यादा टैक्सेबल करना चाहिए। ऐसा लगता है कि पूरा सरकारी तंत्र corporate के लिए है, आप उन्हीं को benefit देना चाहते हैं, उन्हीं को support करना चाहते हैं। So, this partiality towards corporates become very heavy on a common man. यह जनता के बीच common बातचीत का एक विषय बन चुका है। In Pandit Nehru's word, 'The Government is relying on distribution of poverty.' हम poverty को distribute करना चाहते हैं। आप 14th CAG Report on Outstanding Demand on Income Tax Assessee के बारे में सोचिए। कैग की रिपोर्ट एक है। हमारा IT Department डिफंक्ट हो गया है। हमारे Secretary-General, Modi sahib, Head of the IT, Income Tax Ward में थे. Actually IT Department defunct हो गया है। CAG Report का यह कहना है कि 2011 में CAG found 84.3 per cent of outstanding tax demand to be unrecoverable. And, this has now risen to 97 per cent. That is, Rs.19.35 lakh crores is unrecoverable. आप recovery ही नहीं कर सकते। कैग कहता है, despite multiple requests, CBDT refused to share tax defaulter's data from March, 2020 to 2024. अगर आपकी transparency ही नहीं है और CBDT अपना data, जो डिफॉल्टर्स का है, जब CAG से ही share नहीं कर रहा है, तब हम क्या बोलें? कैग यह कह रहा है कि IT department failed to produce records for several high demand cases, including three firms owing about Rs.11,000 crores. आप कैग से छिपाते हैं, आप कैग को बताने के लिए तैयार नहीं हैं। Out of 2,156 audit queries sent by the CAG, कैग ने जो 2,156 क्वैरीज़ भेजीं, उनमें से 81 per cent were unanswered. उनका आन्सर ही नहीं दिया गया, exposing systemic inefficiency in the tax recovery. आप कहते हैं कि हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, आपके टाइम में tax system बहुत अच्छा है, लेकिन इस कैग रिपोर्ट के बाद

मैं क्या सोचूँ और क्या समझूँ? अगर ये 19 लाख करोड़ रुपये, जो हम efficiently collect कर लेते हैं, तो आप सोचिए कि हमारे social sector की spending on health, education, research, Defence, food subsidy, MGNREGA and even a better Kumbh आदि उससे आर्गनाइज़ हो जाते। But, हम हमारा सिस्टम इतना शिथिल हो गया है कि अपनी outstanding demands collect ही नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, अब मैं Indian judiciary पर आता हूं। आप देखिएगा कि 5 crore cases pending हैं। आपने judiciary की तरफ क्या ध्यान दिया है? 2024-25 में आपने Rs.6,461 crores judiciary को दिए थे, 2025-26 में आप Rs.5,850 crores propose कर रहे हैं, यानी आपने कम कर दिया है। महोदय, Cases की, arrears की संख्या बढ़ती जा रही है। यह 5 करोड़ तक पहुँच रही है, इसका बजट कम होता जा रहा है।

महोदय, आपने Mediation Bill पास किया। It is a non-starter. क्योंकि Mediation Bill भी parallel set-up, जैसे court का set-up है, you need a parallel mediation set-up. Where is that set up? Where are mediators? Where is building? जो लोग आएंगे, वे कहाँ बैठेंगे? जितनी सूट्स फाइल होती हैं, उतना मिडिएशन होना चाहिए। That is the law. उतने कोर्ट रूम्स होने चाहिए, उतने mediators होंगे, counsellors होंगे, clients आएंगे, लेकिन आपके पास infrastructure नहीं है, सेट-अप नहीं है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग ही नहीं होती है। We still have more than 5 crore cases pending. Every time, you make a new law. आपको न्यू लॉ से एक impact assessment करना चाहिए कि कितने केसेस generate होंगे।

कोर्ट्स में कितने केसेज़ बढ़ेंगे। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं रहती है। For judges, police and prosecutors, extensive training करनी चाहिए, which is lacking. Then, digital infrastructure for case management and evidence storage, कहाँ पर है? आज अगर चेन्नई में कोई crime होता है और हमें दिल्ली में biometrics से connect करना है कि क्या उस आदमी ने दिल्ली में कभी कोई crime किया था, तो इसके लिए कोई centralized system ही नहीं है। Then, coming to implementation cost for new procedural requirements, मतलब कि आपने हर चीज़ बहुत difficult बनाई हुई है। अगर आप बजट के माध्यम से, judiciary के साथ liberal होते, तो हो सकता है कि एक modern judicial set up आ जाता। मेरा तो कहना है कि Rs.3,000 crores for fast track commercial courts to clear business disputes within 12 months – आपको यह बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि देश पाँच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने, तो यह कैसे बनेगा? लोगों को विश्वास ही नहीं है कि यहाँ पर disputes resolve हो सकते हैं, सालों तक business disputes resolve ही नहीं होंगे। इसके लिए आपका कोई सिस्टम ही नहीं है। आपको 1,500 करोड़ चाहिए to recruit 5,000 new judges in courts and tribunals. Where is that in the Budget? आपको मिनिमम एक हजार करोड़ लगेंगे to establish evening courts in metro cities for contract enforcement cases. अपने बजट के माध्यम से कोई नई सोच तो लाइए। जो systems already collapse कर चुके हैं, उन्हें आप कहाँ address कर रहे हैं? सिर्फ slogan से address हो जाते, तो चीज़ें बहुत पहले ही ठीक हो गई होतीं। हमारा कहना यह है कि around Rs.6,00,000/- crores of investment projects are

stuck in legal battles due to judicial delays. On infrastructure, छः लाख करोड़ के cases pending हैं। Real Estate and infrastructure projects worth Rs.1.3 lakh crores are stuck in land acquisition disputes. Land disputes alone account for 66 per cent of civil cases dealing in infrastructure and industrial projects. ऐसे में, इंडिया में कौन foreign investor आने वाला है, जबकि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया आने वाली है। सर, दुनिया में से कौन आएगा? दुनिया तब आएगी, जब आपका Ease of Doing Business really सामने दिखेगा। उस आदमी को लगना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हो, मेरे साथ गलत हो और मैं कोर्ट-कचहरी गया, tribunal गया, अधिकारी के पास गया, तो मेरी problem solve हो जाएगी। Coming to health care, health care spending remains at 2.1 per cent of GDP, which is barely enough for bandage. I mean, forget a health revolution, bandage के लिए हो जाए, तो बड़ी बात है।

In the UK, the USA, Europe, people pay 40 or 50 per cent taxes and get 100 per cent optimum health care. In India, we pay 50 to 60 per cent taxes, but get no health care. आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं भी देख लीजिए, सब लोग Delhi AIIMS में आना चाहते हैं and Delhi AIIMS is so overcrowded. There is no place to stand. आपको patients के relatives बाहर रोड्स पर और inside metro station मिलेंगे। Surgeries की dates एक-एक साल बाद, दो-दो साल बाद मिलती हैं! मेरे पास रोज requests आती हैं कि सर, हम बचेंगे ही नहीं, तो surgery करवा कर क्या करेंगे? आप किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, किस health mechanism की बात कर रहे हैं? हम CGH Scheme लेकर आए। आप बताइए कि कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स CGH Scheme को accept करते हैं? वे patients को भगा देते हैं। वे कहते हैं कि सालों तक हमारे bills clear नहीं होते हैं। सर, यह बात सबको पता है। Finance Minister allocation for hospitals क्यों नहीं बढ़ाते हैं? About 50 per cent of Indians lack basic health insurance. 20,000 से 75,000 के बीच में जो mid segment वाले लोग हैं, उन्हें ये benefits ही नहीं मिलते हैं। CAG Report में आयुष्मान भारत के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं कि वहाँ पर कितना फ्रॉड चल रहा है।

Coming to education, आपका school drop-out is 15 to 20 per cent. The National Centre of Excellence for Skilling is like throwing a birthday party with one balloon. The Government promises *Viksit Bharat* by 2047, but we want IITs, IIMs and medical colleges today, not in 2047, Sir. So, आप 300 incubation scheme लेकर आए। आप बताइए कि क्या आपने एक unicorn produce भी किया? आप करोड़ों रुपये incubation scheme पर लगा देते हैं, पर आपने इंडिया में unicorn कौन बनाया। मेरा यह कहना है कि आप R&D में बजट नहीं बढ़ाएं। आप R&D में क्या spend करते हैं – 0.64 परसेंट! अगर आप R&D में spend नहीं करेंगे, तो आप बताइए, China, spends 2.4 per cent, the US spends 3.5 per cent, उनसे कैसे compete करेंगे?

गवर्नमेंट का R&D 55 परसेंट है, प्राइवेट सेक्टर का 45 परसेंट है, जबकि यूरोप में 70 परसेंट है। DeepSeek and ChatGPT is the new breakthrough. ...(**समय की घंटी**)...

Breakthrough जो गया है, वह तो अमेरिका और यूरोप में हो रहा है और हम कहते हैं कि हम new era में जा रहे हैं।

सर, मेरे पास कहने को बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : समय हो गया है। अब आप विराजिए।

श्री विवेक के. तन्खा : सर, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि GST को rationalize कीजिए। GST में प्रॉब्लम क्या है, apart from the tax rates, जो without determination लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, इससे पूरी इंडस्ट्री डरी हुई है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री विवेक के. तन्खा : आपका execution खराब है, आपकी प्लानिंग नहीं है और आपकी कोई स्कीम्स नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद, तन्खा साहब। श्री शुभाशीष खुंटिया, अनुपस्थित। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, अनुपस्थित। डा. वी. शिवादासन।

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Respected Chair, the Budget itself is very insufficient. The Government has failed to mobilise the resources. The total Budget is only 14.2 per cent of the GDP. In USA, the expenditure of the Federal Government is 23 per cent of GDP. The Government should mobilize the resources and spend them for the common good. But the Union Government does not have proper vision and proper foresight. Gandhiji was martyred on 30th January. The Budget is presented on 1st of February. We say, 'Gandhiji lives in our hearts.' But can we see Gandhiji in the Budget documents? Gandhiji gave a talisman to us. "Recall the face of the poorest and weakest human being whom you may have seen and ask yourself if the stuff you contemplate is going to be of any use to them." The Budget fails according to Gandhiji's talisman. Gandhiji talked about *Gram Swaraj* but rural India was completely neglected in this Budget. The Government has not spent the allocated amount, Rs. 75,000 crore for the rural sector in 2024-25. They have announced many schemes but they did not spend the money. The Government is not ready to increase the allocation for the MGNREGA by even a single paisa from Rs. 86,000 crore. The Government has been cutting the allocations for employment guarantee scheme. It was Rs. 1.1 lakh crore in 2020-21 but now it is only Rs. 86,000 crore. Each year, they have decreased it. They are telling that MGNREGA is a demand-driven project. But they will give more

money -- that is their announcement -- according to the demand. Since last year, the Union Government has not been ready to allocate more than a single paisa to the MGNREGA scheme. The Union Budget has failed to address the basic issues of the common people. The value of the rupee is decreasing day-by-day. In the history of India, we have never seen such a fall of Indian rupee. The credit goes to the Union Government according to the statements of a former Gujarat Chief Minister. The Government is selling the valuable assets of the nation. The Government plans to raise Rs. 47,000 crores by selling public sector enterprises. They are telling about *Ujjwala Yojana* but the LPG subsidy has been reduced by Rs. 2,600 crore.

Sir, what about the allocation for welfare programs? Only Rs. 12,500 crore have been allocated for the Mid-day Meal Scheme. Sir, the amount allocated last year was Rs. 12,460 crore, but they revised it and reduced the amount to Rs. 10,000 crore. In India, peasants are struggling, but the amount allocated for the Crop Insurance Scheme has been reduced. Fertilizer subsidy has been reduced. The amount meant for irrigation schemes has been reduced. Earlier, it was Rs. 11,840 crore, but now it is only Rs. 10,764 crore. The allocation towards scholarships for *adivasis* and *dalits* has been reduced. The allocation for pre-Matric scholarship has been reduced. They did not increase a single rupee for *Anganwadi* workers, ASHA workers and Mid-day Meal Scheme workers. They have presented a Budget that has completely neglected the rural poor and marginalized. In the banking sector, employees are working day and night, but they are not getting proper remuneration. They are trying to privatize the Life Insurance Corporation through foreign investment.

Sir, I come from Kerala. This Government neglected the tears of the people of Wayanad in Kerala. I would like to remind them that Wayanad is in the Indian Republic. ...*(Interruptions)*... आप राम का नाम बोलते हैं, लेकिन ...(**समय की घंटी**)... Sir, I request the Government to protect the interests of the people of the country. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप समाप्त करें।

DR. V. SIVADASAN: Sir, just a minute. They are trying to reduce the allocations for all the welfare measures. ...*(Interruptions)*... They did not increase a single rupee for the pension scheme.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ। ...(**समय की घंटी**)... माननीय सदस्य, आपका भाषण समाप्त हुआ।

DR. V. SIVADASAN: Sir, give me just one minute. I lost one minute because of the disturbance. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आप अपना भाषण समाप्त करें।

DR. V. SIVADASAN: Sir, they are not ready to increase even a single rupee for the pension scheme. They did not increase even a single rupee for widow pension, pension for elderly persons and pension for the weaker sections. How would they protect the interests of the common people? I request the Government not to sell the assets of the people. Do not sell the nation's legacy to foreign countries. I request the Government to take protective measures for the people.

With these words, I conclude my remarks on the Budget. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : धन्यवाद, डा. शिवादासन। माननीय श्री संजय राउत।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र) : सर, आजकल के जो बजट होते हैं, वे किसी राज्य में चुनाव है, यह देख कर बनाए जाते हैं, चाहे चुनाव दिल्ली का हो, चाहे चुनाव बिहार का हो। उस बारे में कोई तकरार करने की, कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, सब हमारे देश के हिस्से हैं। अब बिहार का चुनाव है, तो अगर बिहार के लिए बजट में कुछ ज्यादा दिया गया है, तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसके साथ सभी राज्यों को भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि बिहार को पिछले बजट में 60,000 करोड़ दिया गया था। मेरे हिसाब से, जो जानकारी मेरे पास है, 60,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था, लेकिन यह सरकार उसमें से कितना खर्च कर पाई है? अब तक 600 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ है, यह जानकारी मुझे किसी ने दी है। अगर यह सही है, तो पैकेज पर पैकेज देकर किसी राज्य को आप इस तरह से अपने कर्ज में या दबाव में लेना चाहते हैं।

सर, हमारी अर्थव्यवस्था को आगामी कुछ वर्षों में 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है और मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, बहुत सी बातें करनी चाहिए, देश की जनता के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, मुझे इस बजट में उसमें बहुत सी कमियाँ दिखती हैं। आप किसानों की इनकम डबल करने का वादा हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस बारे में इस बजट में कोई खास योजनाएँ नहीं हैं। किसानों की कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो माँग है, जिसके लिए आज भी पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, अगर आप यह घोषणा इस बजट में करते, तो जरूर हम उसका स्वागत करते।

सर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, फिर भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी कर्ज में डूबी हुई है। भारत सरकार पर आज भी लगभग 185 हजार करोड़ का कर्ज है, फिर भी सरकार ने कुछ गिने-चुने उद्योगपतियों का लगभग 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज हम अब तक माफ नहीं कर पाए हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था करीब 325 लाख

करोड़ की है और यह जो कर्ज हमने माफ किया है, यह अर्थव्यवस्था के 50 परसेंट के बराबर है। देश के हर व्यक्ति पर आज भी सवा लाख रुपए का कर्ज है।

सर, सरकार कहती है कि यह मिडल क्लास का बजट है, कैसे? आपने 12 लाख तक की इनकम को इनकम टैक्स में छूट दी है, सिर्फ इसीलिए यह बजट मिडल क्लास का बजट नहीं हो सकता। देश की आबादी लगभग 140 करोड़ के पार हो गई है। उसमें 12 लाख इनकम पाने वाले कितने लोग हैं? अगर आज लोग इनकम टैक्स से ज्यादा परेशान हैं, तो जीएसटी से परेशान हैं। जीएसटी का भी सीधा असर इस देश के मिडल क्लास पर हो रहा है। लोग मार्केट में जाते हैं, रोज काम आने वाले सामान खरीदते हैं और हर सामान पर कॉमन लोगों को जीएसटी पे करनी पड़ती है, इसीलिए महंगाई बढ़ गई है। अगर आपने इनकम टैक्स के साथ-साथ, मिडल क्लास के लोगों के लिए जीएसटी के ऊपर भी कोई अच्छा पैकेज दे देते, तो इस देश की जनता सचमुच खुश रहती, क्योंकि आज जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी है, जीएसटी की वजह से व्यापारी खुश नहीं है और जीएसटी की वजह से एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है, जो अपना consumption कम कर रहा है। ये सभी जो बातें हैं, ये जीएसटी से जुड़ी हैं, लेकिन आपने कॉमन पीपल को जीएसटी के मामले में कोई कंसेशन नहीं दिया है।

सर, दूसरी बात यह है कि अगर आप मिडल क्लास की बात करें, तो आज भी यह सरकार 85 करोड लोगों को फ्री राशन दे रही है, यानी ये सभी लोग below poverty line हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई इनकम नहीं है। देश में 15 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वे पूरी तरह से बेरोजगार हैं, उनका कोई इनकम नहीं है और हमारी वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बेरोजगारी के बारे में न तो कोई योजना दी है और न ही बेरोजगारों का कोई नाम लिया है। देश में महंगाई बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए कोई योजना नहीं है। रुपया दिनों-दिन गिर रहा है, उसके बारे में हमारे पास कोई मजबूत योजना नहीं है।

महोदय, अगर हम ये सारी बातें देखें, तो इस बजट में दिखावा ज्यादा है। इसमें दिखावा ज्यादा है, शो ज्यादा है। यह शो इतना ज्यादा है कि यह शो देखकर लोग भूल जाते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं। आप बड़े-बड़े भाषण करते हैं, अच्छी बात है, आपकी सरकार है। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि जब तक इस देश में मिडल क्लास जिंदा है, तब तक यह देश जिंदा रहेगा, क्योंकि इस देश में लड़ने वाला जो आदमी है, वह मिडल क्लास का है। आने वाले दिनों में चाहे वह बजट हो या आपकी योजनाएं हों, मिडल क्लास को ध्यान में रखकर, जो लोग below poverty line हैं, उन सबको ध्यान में रखकर आपको अपनी योजनाएं तैयार करनी पड़ेंगी, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : राउत साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मस्तान राव यादव बीडा।

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of our TDP Party and our leader, hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Nara Chandrababu Naidu garu, I am participating in the Discussion on the Union Budget for 2025-26. The Union Budget, 2025-26 marks a significant milestone in

India's economic journey under the visionary leadership of our hon. Prime Minister, Narendra Modi*ji* and the hon. Finance Minister, Nirmala Sitharaman*ji*. This development-orientated Budget reaffirms the Government's commitment to economic growth, social welfare and fiscal prudence.

Sir, first, I will speak on Andhra Pradesh's scenario as I don't want to waste much of time discussing other things. First, I will speak on Budget allocation and its impact. Recognising hon. Chief Minister Chandrababu Naidu's pivotal role in India's economic growth, the Union Budget 2025-26 has allocated significant funds for the State across multiple Ministries and schemes.

These allocations are in line with Vision 2047 of the Government of Andhra Pradesh, that is, Viksit Andhra Pradesh 2047, which emphasizes infrastructure growth, agricultural modernization, employment generation and digital transformation.

As per the wish of our hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Garu, I would like to highlight the key Ministry-wise allocation for Andhra Pradesh. For the Ministry of Rural Development, the allocation is Rs.12,000 crore (MGNREGS, PMAY-Rural, PMGSY), which is an increase of 9.1 per cent from Rs.11,000 crore in the previous year. For the Ministry of Road Transport and Highways, the allocation is Rs.18,500 crore (expansion of NHs, Expressways), which is an increase of 8.8 per cent from Rs.17,000 crore in the previous year. For the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, the allocation is Rs.10,000 crore (PM-KISAN, Crop Insurance, Irrigation), which is an increase of 7.5 per cent from Rs.9,300 crore in the previous year. For the Ministry of Jal Shakti, the allocation is Rs.6,800 crore (Jal Jeevan Mission, Polavaram Project), which is an increase of 6.3 per cent from Rs.6,400 crore in the previous year. For the Ministry of Education, the allocation is Rs.8,500 crore (new IIT, Skill Development), which is an increase of 7.6 per cent from Rs.7,900 crore in the previous year. For the Ministry of Health and Family Welfare, the allocation is Rs.7,200 crore (AIIMS expansion, Rural Healthcare), which is an increase of 8.3 per cent from Rs.6,650 crore in the previous year.

As per the demand of our hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, I would like to talk about the approved projects in Andhra Pradesh. The Budget clearly reflects the Government's focus on infrastructure development, with key allocations directed towards infrastructure by providing Rs.12,000 crore for roads under Bharatmala Phase-II, which is 10 per cent increase from Rs.10,900 crore in the previous year. For Metro and Railways, it provides Rs.4,000 crore for Visakhapatnam Metro and Rail Network Expansion, which is 7.5 per cent increase from Rs.3,720 crore in the previous year. For Renewable Energy, it provides Rs.5,000 crore for

Green Energy Corridor, which is 8.7 per cent increase from Rs.4,600 crore in the previous year. For Urban Development, it provides Rs.5,000 crore under the Smart Cities Mission, which is 6.8 per cent increase from Rs.4,680 crore in the previous year. For the Polavaram Irrigation Project, it provides Rs.6,500 crore additional funding, which is 5.4 per cent increase from Rs.6,170 crore in the previous year.

These allocations reaffirm the idea of our hon. Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Garu, for strong co-operative federalism between Andhra Pradesh and the Central Government. I would like to quote the legendary leader Shri N.T. Rama Rao, who said, "Development is the right of every citizen, and governance must ensure it reaches every corner of the society." This Budget fulfills that vision by empowering Andhra Pradesh's economy and infrastructure. These initiatives support Aatmanirbhar Andhra Pradesh, leveraging the Centre's vision to transform the State into an innovation and technology hub.

With deep gratitude to the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, the hon. Home Minister, Shri Amit Shah, the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, and our hon. Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu, we acknowledge their steadfast commitment to India's progress and Andhra Pradesh's development. Jai Bharat! Jai Andhra Pradesh! Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : डा. भागवत कराड़।

डा. भागवत कराड़ (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और हमारे हाउस लीडर जे. पी. नड्डा जी तथा पार्लियामेंटरी मिनिस्टर माननीय किरेन रिजिजु जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस बजट पर बोलने के लिए वक्त दिया है। माननीय वित्त मंत्री महोदया का यह दूसरा रिकॉर्ड बन रहा है। जब उन्होंने 2024 में बजट पेश किया था, तब उन्होंने एक महिला वित्त मंत्री के रूप में सातवाँ बजट पेश किया था और अभी उन्होंने आठवाँ बजट पेश किया है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का दिल से अभिनन्दन करना चाहता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है और भारत में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। प्रधान मंत्री जी का 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उसके लिए हम सभी को मिल कर काम करना पड़ेगा।

8.00 P.M.

सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह यह प्रधान मंत्री जी के तीसरे टर्म का पहला बजट है, उसी तरह से यह बजट इस सेंचुरी का...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : आपका भाषण कल जारी रहेगा।

The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Tuesday, the 11th February, 2025.

The House then adjourned at eight of the clock till eleven of the clock
On Tuesday, the 11th February, 2025